

दिल्ली में 8 एग्जिट पोल में बीजेपी बना रही सरकार, दो में 'आप'

AGENCY NEW DELHI :

बुधवार को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई। वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होते ही एग्जिट पोल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 10 एग्जिट पोल आए हैं। 8 में भाजपा को बहुमत मिलता दिखाया गया है। 2 में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने का अनुमान है। एग्जिट पोल के पोल आफ पोल्स में भाजपा को 39, आप को 30 और कांग्रेस को एक सीट मिलने का अनुमान है। जेवीसी और पोल डायरी ने अपने एग्जिट पोल में अन्य को भी 1-1 सीट मिलने का अनुमान बताया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, शाम 5 बजे तक 57.85 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले। सबसे ज्यादा नार्थ-ईस्ट दिल्ली में 63.83 प्रतिशत और सबसे कम साउथ-ईस्ट में 53.77 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 12 सालों में यह सबसे कम वोटिंग हो रही है। दिल्ली विधानसभा के पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है।

विधानसभा चुनाव में 57.5% हुई वोटिंग, ईवीएम में बंद हो गई 699 उम्मीदवारों की किस्मत नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में सर्वाधिक 63.83% और साउथ-ईस्ट में सबसे कम 53.77% मतदान

सर्वे एजेंसी	AAP	भाजपा+	कांग्रेस
मैट्रिज	32-37	35-40	0-1
पीपुल्स इनसाइट	25-29	40-44	0-1
पीपुल्स पल्स	10-19	51-60	0-0
जेवीसी पोल्स	22-31	39-45	0-2
P MARQ	21-31	39-49	0-1
चाणक्य स्ट्रेटजीज	25-28	39-44	2-3
पोल डायरी	18-25	42-50	0-2
डीवी रिसर्च	26-34	36-44	0
वीप्रिप्साइट	46-52	18-23	0-1
माइंड ब्लिंक	44-49	21-25	0-1

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई दिग्गजों ने किया मतदान

सुबह सात बजे से शुरू हुए मतदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, केंद्रीय मंत्रियों एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिथी और आम आदमी पार्टी के



सीलमपुर में फर्जी मतदान की शिकायत पर हंगामा 'आप' के दो विधायकों पर दर्ज हुई एफआईआर

भाजपा ने आरोप लगाया है कि सीलमपुर में बुर्कें में महिलाओं से फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। इस दौरान आप और भाजपा समर्थक एक-दूसरे से भिड़ गए, जिससे हंगामा होने लगा। बृथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने माना कि किसी और के नाम पर दूसरे लोग वोट डाल गए। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जांच में कहा कि नाम एक जैसे होने की वजह से कंप्यूजन हुआ। इसके बाद यहां पुलिस जांच कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू एन ब्लॉक में 2000-3000 रुपये बांटे गए और लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई। यह सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। साल 2013 में 65.63 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। 2015 में 67.12 प्रतिशत

और 2020 में 62.59 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। तीनों बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इस बार 57.85 प्रतिशत वोटिंग हुई है। आयोग की ओर से बताया गया कि गुरुवार की सुबह तक फाइनल आंकड़ा सामने आएगा। मुस्तफाबाद में सबसे अधिक 66.68 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि करोल बाग में सबसे कम 47.40 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग के दौरान आप के 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिनेश मोहनिया के खिलाफ एक महिला ने फ्लाइंग किस देने का केस दर्ज कराया। ओखला विधायक अमानुल्लाह खान के खिलाफ आचार सहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है।

SHARE	
सेंसेक्स	: 78,271.28
निफ्टी	: 23,696.30

SARAF	
सोना	: 6,795
चांदी	: 107.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

झारखंड के खिलाड़ियों ने लॉन बॉल में जीते तीन स्वर्ण

RANCHI : राइटमंडल खेल 2022 में महिला फोर्स लॉन बॉल्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा लवली चौबे और रुपा तिकौं ने बुधवार को देहरादून में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को सोने का तमगा दिलाया। झारखंड ने लॉन बॉल्स प्रतियोगिता के पांचवें दिन महिला फोर्स फाइनल में पश्चिम बंगाल को 18-8 से हराया। झारखंड की टीम की दो अन्य सदस्य रेशमा कुमारी है और कविता कुमारी हैं। झारखंड ने बुधवार को लॉन बॉल्स में तीन स्वर्ण पदक जीते। दिनेश कुमार और सुनील बहदुर की झारखंड की पुरुष जोड़ी ने विश्वज्योत खोड और बिमान नाथ की जोड़ी को फाइनल में 25-4 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। झारखंड को तीसरा स्वर्ण बसंती कुमारी ने दिलाया जिन्होंने महिला अंडर-25 फाइनल में असम की सुरजना बरुआ को 21-20 से शिकस्त दी। दिल्ली के अनंत शर्मा, अपूर्व शर्मा और अभिषेक घुग ने झारखंड के आलोक लाकड़ा, अभिषेक लाकड़ा और प्रिंस महतो की टीम को फाइनल में 25-8 से हराकर पुरुष ट्रिपल स्पर्धा का स्वर्ण जीता।

5 अतिरिक्त जजों को स्थायी करने की मिली मंजूरी

NEW DELHI : बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मद्रास और तेलंगाना उच्च न्यायालयों के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में बुधवार को कॉलेजियम की बैठक हुई। कॉलेजियम द्वारा जारी बयान के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने पांच फरवरी, 2025 को अपनी बैठक में मद्रास उच्च न्यायालय में मौजूदा समय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत न्यायमूर्ति वैक्कटाचारी लक्ष्मीनारायणन और न्यायमूर्ति पेरियासामी वडामलाई को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए दो दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में यह समिट हो रहा है। देश-विदेश की कई गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने समिट को संबोधित किया। कहा कि जिस तेजी से आज तकनीक बदल रही है, उसमें एक मजबूत एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए राज्यों के बीच बेहतर संबंध, समन्वय तथा भागीदारी होना अत्यंत जरूरी है। इस कड़ी में राज्यों में होने वाले ग्लोबल बिजनेस जैसे समिट की नियंत्रण भूमिका होती है। आज के समय में देश के आर्थिक विकास में झारखंड हम रोल निभा रहा है।

इस प्रकार के समिट से एक राज्य का दूसरे राज्यों तथा अन्य देशों से बेहतर बनते हैं व्यापारिक रिश्ते

➤ देश-विदेश की कई गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में किया संबोधित

➤ उद्यमियों और निवेशकों को झारखंड आने का दिया निमंत्रण

➤ कहा- निवेशकों के सहयोग से झारखंड के समग्र विकास की दिशा में बढ़ सकते हैं आगे

➤ विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए राज्यों के बीच बेहतर संबंध, समन्वय तथा भागीदारी होना अत्यंत जरूरी

➤ झारखंड राज्य को और आगे ले जाने के लिए नए सिरे से कर रहे पहल

➤ बंगाल-झारखंड एक जैसी गतिविधियों के साथ बढ़ रहे हैं आगे

देश का 40% खनिज संसाधन उपलब्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है, जहां देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज संसाधन पाया जाता है। कई खनिज एवं उद्योगों के लिए जरूरी रॉ मटीरियल्स का झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां कई खनिज आधारित उद्योग लंबे समय से स्थापित हैं। कई औद्योगिक घरानों ने यहां निवेश किया है। लेकिन, वर्तमान परिवेश में इस राज्य को और आगे ले जाने की जरूरत है। इसके लिए यहां नए-नए उद्योग लगे, इसके लिए नए सिरे से पहल कर रहे हैं।



उद्योगपति मुकेश अंबानी से हाथ मिलाते सीएम हेमंत

मलटोटी पुल के पास बने डायवर्जन पर चपेट में आ गए दोनों विद्यार्थी मांडर में ट्रक ने बाइक को रौंदा, दो स्टूडेंट की मौत

PHOTON NEWS RANCHI :

बुधवार को रांची के मांडर में दर्दनाक हादसा हो गया। मांडर थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार दो दो विद्यार्थियों को रौंदा दिया। इस हादसे में एक युवक और युवती की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान देवदास मंडल और ऐश्वर्या के रूप में हुई है। दोनों ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। छात्र की उम्र 25 साल, जबकि छात्रा की उम्र 23 साल थी। दोनों मृतक सेंट्रल युनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के स्टूडेंट थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुआ है। मामला मांडर थाना क्षेत्र के मलटोटी पुल के पास का है। यहां बने डायवर्जन पर ट्रक की चपेट में दो छात्र-छात्राएं आ गए। घटना बुधवार को सुबह लगभग 9 बजे की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर हंगामा कर दिया। शव को घटनास्थल पर रखकर लोगों ने घरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

ऑन द स्पॉट गई जान, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे दोनों मृतक



आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

स्थानीय लोगों ने बताया कि कोयले से लदा ट्रक डायवर्जन से गुजर रहा था। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रहे दोनों छात्र और छात्रा ट्रक की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया।

चूर-चूर हो गई बाइक

स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक पर सवार सेंट्रल युनिवर्सिटी के दोनों छात्र पुल के पास बने डायवर्जन से गुजर रहे थे, इसी दौरान एक मालवाहक ट्रक ने दोनों को पीछे से कुचल दिया। दोनों छात्रों की मौत पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि छात्रों की बाइक पूरी तरह से टूटकर बर्बाद हो गई। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर और



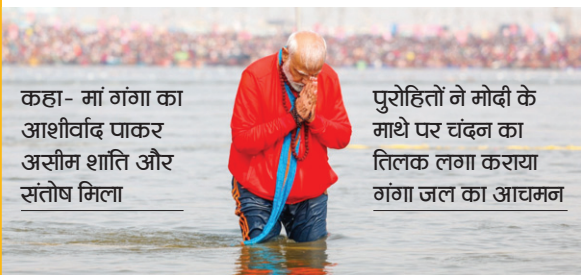
संविधान को खत्म करना चाहते हैं भाजपा-आरएसएस के लोग : राहुल गांधी

PATNA : बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय

- स्वतंत्रता सेनानी व दलित नेता जवाहरलाल चौधरी की जयंती पर किया संबोधित
- स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर संविधान को खत्म करने की मंशा रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को माथा टेक कर और आरएसएस के लोग अबेडकर के प्रति सम्मान का दिखावा कर लोगों की

आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वह स्वतंत्रता सेनानी एवं दलित नेता जवाहरलाल चौधरी की जयंती के अवसर पर घटना में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। राहुल ने कहा, मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हर संस्था और तंत्र में नेतृत्व के स्तर पर दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग दिखें। मैं वह दिन देखना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान की शीर्ष दस कंपनियों के मालिक दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग से हों और मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ तथा आगे भी लड़ता रहूंगा। राहुल ने कहा, मैं बिहार के दलित और पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूँ कि यह जो संविधान है, यह अबेडकर और गांधी जी की देन है। संविधान में आपके हजारों साल का दर्द छुपा है। जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको

महाकुंभ : प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी



NEW DELHI @ PTI :

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद पाकर भरे मन को असीम शांति और संतोष मिला। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संगम में स्नान करते समय प्रधानमंत्री को पूरी बांह का केसरिया रंग का कुर्ता और नीले रंग का पायजामा पहने देखा गया। उन्होंने रुद्राक्ष की माला से जाप भी किया। उनके गले में भी रुद्राक्ष की एक माला थी। उन्होंने दूध से गंगा का अभिषेक किया और माला फूल चढ़ाकर आरती की। इसके बाद पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और उन्हें गंगा जल का आचमन कराया। संगम में स्नान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजन-अर्चन किया। काले कुर्ते और केसरिया पटके एवं हिमाचली टोपी पहने प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच त्रिवेणी संगम में अश्वत, नैवेद्य, पुष्प,

➤ स्नान करते समय पूरी बांह का केसरिया रंग का कुर्ता और नीले रंग का पायजामा पहने दिखे प्रधानमंत्री

➤ दूध से गंगा का अभिषेक किया, फूल-माला चढ़ाकर की आरती

फल और लाल चुनरी अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संगम स्थल पर तीनों नदियों की आरती की। प्रधानमंत्री ने द्वापरासहस्र पर एक पोस्टर में कहा, प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा-अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख-समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की।

मेडिकल रिसर्च फेफड़ों और आंत के निचले हिस्से में कैंसर का बन रहे कारण

सेहत के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहे प्लास्टिक के पार्टिकल्स

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :

हमारी जीवन शैली और प्रदूषित भोजन के कारण सेहत को कई स्तरों पर संकट का सामना करना पड़ता है। सेहत पर हवा, पानी और ध्वनि के प्रदूषण का असर तो पड़ता ही है, सड़कों पर चल रही गाड़ियों के टायर और ब्रेक घिसने से निकले पार्टिकल्स भी खतरनाक बीमारी पैदा कर रहे हैं। हाल में हुए मेडिकल रिसर्च में ये तथ्य सामने आए हैं कि ऐसे पार्टिकल्स को माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं और इनसे कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है। वैज्ञानिकों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, हवा में मौजूद प्लास्टिक के महीन कण यानी माइक्रोप्लास्टिक, स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इन पर किए एक नए अध्ययन में खुलासा किया है कि हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स कोलन (आंत का निचला हिस्सा) और फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। गाड़ियों के टायर और ब्रेक घिसने से निकले महीन कण इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

गाड़ियों के टायर और ब्रेक घिसने से हवा में तेजी से फैलते हैं माइक्रो प्लास्टिक सांसों के जरिए शरीर के आंतरिक अंगों में प्रवेश कर धीरे-धीरे पैदा करते हैं रोग

➤ जानवरों के साथ इंसानों के स्वास्थ्य को भी समान रूप से करते हैं प्रभावित

➤ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों की लंबे समय तक की गई स्टडी में हुआ खुलासा



महिलाओं और पुरुषों में बांझपन की भी बड़ी वजह बन सकते हैं ये महीन कण

➤ तीन हजार शोधों की समीक्षा के बाद वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की है विस्तृत जानकारी

रिसर्च में यह जानकारी दी गई है कि वैश्विक रूप से टायरों से हर साल करीब 2907 किलो टन माइक्रोप्लास्टिक्स का उत्सर्जन हो रहा है। ब्रेक से करीब 175 किलो टन का उत्सर्जन होता है। इन माइक्रो प्लास्टिक्स का ज्यादातर हिस्सा पूर्वी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी चीन, भारत, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के बड़े शहरों से उत्सर्जित हो रहा है। ब्रेक से इन शहरों में भारी संख्या में वाहन सड़कों पर ढीलते हैं।

RANCHI : नगर निगम राजस्व शाखा के सेक्शन प्रभारी व कर संग्रहक दिलीप शर्मा के मोरहानाबादी में बंद आवास से 50 हजार नकद व तीन लाख रुपये के सोने के जेवरत चोरी हो गए। दिलीप जब घर पर पहुंचते तो मुख्य द्वार का ताला टूटा पड़ा था। कमरे में बक्शे का ताला टूटा पड़ा था और 50 हजार नगदी के अलावा सोने के जेवरत गायब थे। उन्होंने मगलगांव को बरिय्यातू थाने में केस दर्ज करवाया है।

**उद्यान में सैकड़ों किस्म के 20 हजार से अधिक गुलाब के फूल
आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा राजभवन
का उद्यान, 12 तक ले सकेंगे अद्भुत नजारे का आनंद**

गुलवार से राधेभवन की उड़ान आम लोगों के लिए फिर से खुल जायगा। 12 फरवरी तक लोग हाँ के अश्रुत नज़ारे का आनंद ले सकेंगे। कोई भी व्यक्ति राजभवन के गेट नंबर दो से सुबह 10 बजे से सड़क के एक बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश आवश्यक जांच के बाद ही मिलेगा। सभी आगंतुकों को अपना परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। उड़ान सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक खुला रहेगा। आगंतुकों को अधिकतम 30 मिनट तक उड़ान में रहने की अनुमति मिलेगी। परिसर में फूलों-झाड़ों वाली, नौ म्यूजिकल फव्वारा, महाना गांधी औषधीय उद्यान, गुरु गोविंद सिंह वाटिका, ओकिंड गाउँ, अशोक उद्यान, अकबर गाउँ, बुद्ध गाउँ, मुर्ती गाउँ, बिरसा मण्ड, लोहस छिज आदि देखने योग्य हैं। इसके अलावा देश के मनोरंजक के लिए चिल्ड्रेन पार्क भी है।

**राजभवन के गेट नंबर 2 से दिन में 10 से एक बजे तक होगी एंट्री
अधिकतम 30 मिनट तक उद्यान में रहने की मिलेगी अनुमति**

- प्रवेश करने वालों को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य
- बच्चों के मनोरंजन के लिए चिल्ड्रेन पार्क
- अकबर गार्डन, बुद्ध गार्डन, मूर्ति गार्डन, बिरसा मंडप, लोटस ब्रिज आदि देखने योग्य



52 एकड़ में फैला है राजभवन, 1930 में हुआ था इसका निर्माण

बता दें कि राजबनस लगभग 52 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसका निर्माण 1930 में हुआ था। आम लोगों के लिए सबसे पहले उद्यान वर्ष 2004 में खोला गया था। उस वक़्त सहस्रों सिक्के रज़ी ख़ारखंड के राज्यपाल थे। इस उद्यान में सैकड़ों किस्म के 20 हजार से अधिक गुलाब के फूल हैं। सौजन्य फल की भी भरमार है। इतने में कृत्रिम ओंटोपॉस, कृत्रिम पहाड़-झरने, दीवारों पर बने सौराष्ट्र के पेंटिंग्स, महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमा, युद्ध में

उपयोग किये गये टैंक, विशालकाय चरखा, एमआईजी 21 विमान, पीला बांस, रुद्राक्ष, कल्पतरु, स्ट्रॉबेरी, इलाइची, तेजपत्ता, संतरा, मौसमी, सेव, चीकू, काजू, जामुन, कपूर, लेमन ग्रास, चंदन, लौंग, दालचीनी आदि के पेड़ हैं।

जमीन विवाद में जताई जा रही हत्या की आशंका, पूछताछ जारी
नगड़ी डबल मर्डर मामले में पुलिस
ने चार लोगों को लिया हिरासत में

मंगलवार की रात रांची के नगड़ी में हुए दोहरे हत्याकांड को जमीन विवाद के चलते अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। हत्या की गुथी सुलझाने के लिए रांची एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। रांची के नगड़ी में हुए दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में रांची पुलिस की टीम आधा दर्जन लोगों से पूछताछ कर रही है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा खुद मामले पर नजर रखे हुए हैं। डबल मर्डर केस की गुथी सुलझाने के लिए रांची पुलिस को जो भी सुराग मिल रहा है, उसके आधार पर तुरंत ताबड़तोड़ छापेमारी भी की जा रही है। रांची के सीनियर एसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि दोहरे हत्याकांड मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, सभी से पूछताछ की जा रही है। जमीन से लेकर आपसी रंजिश तक हर एंगल से जांच की जा रही है।

हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए एसएसपी ने किया एसआईटी का गठन



अचानक पहुंचे अपराधी, गोली मार हो गए फरार

रिम्स में मौजूद मुक्त मनोज की बहन प्रीति ने बताया कि वह घर में खाना खा रही थी, इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जब वह दौड़कर वहां पहुंची तो बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप दोनों जमीन पर पड़े थे। अनन-कच्छप ने दोनों को अस्पताल लाया गया लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। 30 वर्षीय मनोज मुंडा और 32 वर्षीय बुधराम मुंडा चाचा-भतीजा थे। प्रीति के अनुसार हत्याओं ने बमूश्किल तीन से बार मिनट में दोनों को गोली मार दी और भाग गए। ऐसा लगा रहा है जैसे वे काफी समय से दोनों की रेहों कर रहे थे। जैसे ही घरखली पूजा विसर्जन की भीड़ कम हुई, मनोज

और बुधराम को गोली मार दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप मजदूरी का काम करते थे। जब दोनों को गोली मारी गई, तो सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली मारने वालों को किसी ने नहीं देखा। गोली लगने के बाद दोनों तड़प रहे थे।

महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद, प्राथमिकी दर्ज

RANCHI : रांची में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स महिला को रांची से मारने की धमकी दे रहा है। जिस महिला को धमकी दी जा रही है उस दुर्बलहाव किताब जा रहा है, वह रांची सिविल कोर्ट की अधिवक्ता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अक्षर रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के डंगरा टोली निवासी शिबु काना पूनम कुमारी ने जमीन दलाश शंभु का संज्ञ संज्ञ पर जानलेवा हमला व गाली गलौज करने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी के लिए अप्रीत दिया है। रांची सिविल कोर्ट की अधिवक्ता पूनम कुमारी के मुताबिक, पुश्तनी जमीन से संबंधित विवाद को लेकर उनके रिश्तेदार शंभु ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उन्हें कोई लगी है। इतना ही नहीं उसने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अधिवक्ता पूनम कुमारी के प्रति भी रांची सिविल कोर्ट के वकील हैं। अधिवक्ता पूनम कुमारी ने लोअर बाजार थाना में लिखित शिकायत दी है।

कांटाटोली फ्लाईओवर पर प्रवेश व निकासी के लिए बन रहे दो रैंप



कांटाटोली फ्लाईओवर की ऊपर सड़क के निर्माण की प्रक्रियययन अब पूरी हो रही है। कुछ दिनों के वाहन लेकर सड़क पर सीधे पहुंचा जा सकेगा। फ्लाईओवर पर प्रवेश व निकास के लिए दो रैंप बनाए जा रहे हैं। पहला रैंप योगदा सत्यंग आश्रम के कांटाटोली की ओर जाने वाले फ्लाईओवर लेन पर वाईपसीसी के समीप और दूसरा शांति नगर से बहू बाजार होते हुए योगदा सत्यंग आश्रम की ओर जाने वाले फ्लाईओवर लेन पर खदगढ़ा बस स्टैंड के समीप भारतीय इंक्लेव के समीप होगा। जुडको की ओर से फ्लाईओवर पर चढ़ने व उतरने के लिए 3.5 मीटर चौड़े दो रैंप का निर्माण कराया जा रहा है। फ्लाईओवर की कुल लंबाई के आधे हिस्से में ये रैंप फ्लाईओवर से जुड़ेंगे।

इसके लिए फ्लाईओवर पर 16.5 मीटर स्पेस को फिलहाल टेम्परी लॉक कर छोड़ दिया गया है। रैंप से फ्लाईओवर पर चढ़ने

वाहनों के आवागमन

- वाहन चालकों के आने-जाने की परेशानी की जाएगी दूर
- वाहनों के उतरने व भारती इन्वेल्व के समीप चढ़ने के लिए बनाया जा रहा रैंप
- 3.5 मीटर चौड़े दो रैंपों का कराया जा रहा निर्माण
- 30 मीटर हिस्से पर ट्रैफिक के साथ जुड़ेंगे रैंप से चढ़ने वाले वाहन

वाले बहान पलाईओवर के लेन पर 30 मीटर की चौड़ाई में ट्रैफिक के साथ मजूर करेंगे। बहानों के आवागमन को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए संबंधित स्थल पर साइनेज को सुगम जाएगा। वाईएमसीए के समीप बनावे जा रहे रैप से योगदा तत्संग आश्रम से कांटाटोली चौक की ओर जाने वाले बहाने उत्तरकर कांटाटोली चौक, पुरुलिया रोड, लालपुर, सामलोंग, नामकुम व कचहरी चौक की ओर जा सकेगें।

वाहनों के आवागमन के बढ़ने की सभावना

दूसरे रैप से नामकुम, सामलौग, काटाटोली चौक, कवहरी चौक, पुरकालिया रोड, लालपुर की ओर से आने वाले वाहन खादगढ़ा बस स्टैंड के प्रवेश द्वार से कुछ देर आगे बढ़कर रैप के सहारे पलाइओवर पर रुकें पाएंगे। रैप का निर्माण होने के बाद काटाटोली पलाइओवर के नीचे 60 प्रतिशत व पलाइओवर पर 40 प्रतिशत वाहनों का आवागमन बढने की सभावना जताई जा रही है।

मथिया में सरकारी बस स्टैंड से गन्तव्य वाले एसी बस भी पलाइओवर का उपयोग कर रैप के सहारे काटाटोली चौक पहुंच पाएंगे।

संभावना यह भी जताई जा रही है कि कनेक्टिंग पलाइओवर का निर्माण होने के बाद मैन रोड में वाहनों का दवाव कम होगा। अधिकांश वाहन दालक समय की बचत व ईंधन की कम खपत के लिए मेकान चौक से सिरमोटी पलाइओवर व कनेक्टिंग पलाइओवर से होते हुए सीधे अपने-अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

पाइपलाइन शिपिंग का काम खानदारा बस स्टैंड से गंधू दूर ओर जुड़को की ओर से इन दिनों माइनर आभोरब्रिज व पाइपलाइन शिपिंग काम तेजी से करवाया जा रहा है। एक माह में माइनर ब्रिज व पाइपलाइन शिपिंग का काम पूरा होने की संभावना जताई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर डीजीपी की हुई नियुक्ति : मरांडी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर दो अहम मुद्दों को लेकर हमला किया है। पहला मुद्दा राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर है। मरांडी ने सोशल मीडिया एकस पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया है। कदाचार में लिप्त अनुराग गुप्ता वृषीपससी की अशुश्रूषित सूची में नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें डीजीपी बनाया गया है। दूसरा मुद्दा रामगढ़ के गोला में हुए सख्खवी पूजा विवर्जन जुलूस पर हिंसक हमले का है। उन्होंने आरोप



लगाते हुए बताया कि मंगलवार को रामगढ़ के गोला में सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस पर एक विशेष समुदाय द्वारा हिंसक हमले में दो श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीण शांतिपूर्वक मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जित करने जा रहे थे लेकिन समुदाय विशेष के लोगों द्वारा रास्ता रोककर जुलूस में जा रहे बच्चों, महिलाओं पर हमला किया गया।

आंधी-तूफान और लू को विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने का फैसला

सांसद संजय सेठ लॉन्च करेंगे नमो ई-लाइब्रेरी

यह सुखद है कि राजधानी रांची के नमो बुक बैंक में 3.60 लाख किताबें अब तक जमा हो चुकी हैं। प्रो. झारखंड के 80 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने यहां से किताबें ली हैं। केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ जल्द ही नमो लाइब्रेरी की सौगात देंगे। संजय सेठ ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। संजय सेठ ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में 68 करोड़ की लागत से सीसीएल और कोल इंडिया की मदद से अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनी है। उन्होंने यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047

कहा- विकसित भ



तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में उनका (संजय सेठ का) भी गिलहरी प्रयास शामिल रहेगा। सेठ ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने नमो

महीने में 5-6 लेक्चर की भी करेंगे व्यवस्था

सांसद ने कहा कि वह महीने में 5-6 लेक्चर की भी व्यवस्था करेंगे। देश के अपनी फील्ड के एक्सपर्ट को बुलायेंगे और उनका लेक्चर होगा, जिसका लाभ स्टूडेंट्स को मिलेगा। रांची के सांसद ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासी विकसित भारत का सपना देखें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया, तो पूरी दुनिया में स्वच्छता एक आंदोलन बन गया। मोदी जी ने कहा

कि योग करो, तो पूरी दुनिया योग करने लगी। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटा अनाज खाओ, सभी लोग मोटा अनाज खाने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि फूल बरसाओ, तो सभी फूल बरसाने लगे। संजय सेठ ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाओ, घंटी बजाओ, तो लोगों उनकी बात सनकर वह सब कुछ किया।

आवेदन के लिए पात्रता

इस योजना के तहत लाभार्थी लिए आरित
व्यक्तिगत आवस निर्माण के आधार
आवेदन स्वीकार किया जा रहे हैं।
पात्रता, अर्हता और आवश्यक
दस्तावेजों के संबंध में विस्तृत विवरण
भी निगम में उपलब्ध करा दी है।
आवेदक के परिवार में पति, पत्नी और
अविवहाहित बच्चे शामिल होंगे। रांची
नगर निगम क्षेत्र में शासन करने वाले
ऐसे परिवार (निन्का) अपना पक्का घर
नहीं है, पात्र होंगे। इसके अंगत, देश
में कहीं भी किसी भी सदस्य के नाम
पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख
रुपये से कम होनी चाहिए।



जरूरी होंगे ये दस्तावेज

आवेदक का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। आवेदक और उसके परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए।

आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वोटर कार्ड की छायाप्रति। आवेदक के माता-पिता और पति-पत्नी के आधार कार्ड की छायाप्रति।

जमीन का दस्तावेज (खतियान, डीड, वंशशायली, बंटवारा नामा आदि)।

जमीन का अद्यतन लगान रसीद। अंचल प्रयालय से निर्गत या प्रमाण प्राप्त।

ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं आवेदन

इच्छुक पात्र आवेदक लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रांची सुनिश्चितपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर सुओमोटो में प्रेस रिलीज पर जाकर फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन का प्रिंट आउट लेकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रांची नगर निगम के पीएमएवाई यू कोषांग में जमा कराए सुनिश्चित करें। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न घटकों में से एक ही घटक का लाभ ले सकते हैं।

मुआवजे में जोड़ा गया ब्याज दी गई राशि का हिस्सा, अलग नहीं कर सकते : हाईकोर्ट



मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में राशि और ब्याज रहित राशि के बीच कोई अंतर नहीं है। एक बार ब्याज को उस राशि में शामिल कर लिया जाता है, जिसके लिए अबांदा दिया जाता है तो उस अलग नहीं किया जा सकता। वह फैसला सिविल न्याय के अनुच्छेद 227 के तहत भूमि अधिग्रहण निषादन मामले में ट्रावल कोर्ट द्वारा याचिका अंश रद्द करने के लिए दायर की गई थी। इसके लिए दायर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पठित निर्णय के आधार पर

गणना चार्ट के विरुद्ध डिस्ट्रो धारक की गणना पर आपसित खारिज कर दी गई थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया कि 1 मई 2013 से 31 अगस्त 2020 तक 15% प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 3,27,765.12 रुपये का भुगतान करना था। लेकिन, रूसीसीएल ने गणना चार्ट तैयार किया, जिसमें 1 मई 2013 से 31 जनवरी 2023 तक 15% ब्याज की गणना केवल 2,75,896.66 रुपये की मूल गति पर की गई।

समाचार सार

वन की रक्षा करना जरूरी : विधायक जगत माझी

MANOHARPUR : सारंडा वन प्रमंडल के तत्वावधान में बुधवार को ग्राम तिमरा में अग्नि से वनों की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता सह जनसंपर्क कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य अतिथि विधायक जगत माझी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा वन हमारी प्राकृतिक संपदा है। इसकी रक्षा और सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। विधायक ने अपने दिवंगत पिता देवेंद्र माझी के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा और उस पर जंगल के लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन किया था। आज समय की मांग है कि उनके सपनों को साकार करने के लिए वन विभाग के साथ तालमेल बिठा कर जंगल को बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला परिषद की उपाध्यक्ष रंजीत यादव, डीएफओ अभिरुप सिन्हा, प्रशिक्षु आईएफएस अनुराधा मिश्रा, कोयना वन क्षेत्र पदाधिकारी रामनंदन राम, गुवा वन क्षेत्र पदाधिकारी परमानंद रजक आदि उपस्थित रहे।

पुआल में लगी आग, घर भी जला

CHAKRADHARPUR : चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत भरनियां गांव में बुधवार को आग लगने के कारण हजारों रुपये की पुआल जलकर राख हो गई। इस घटना में घर भी जल गया। जानकारी के अनुसार भरनियां गांव निवासी दुर्गा सरदार घर के बगल में रखी पुआल में आग लग गई थी। ग्रामीणों ने तत्काल झोपड़ीनुमा घर में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखे सामान चलकर राख हो चुके थे। कांग्रेस नेता विजय सिंह सामड ने कहा कि पीड़ित परिवार काफी गरीब है। अब परिवार खुले आकाश में रहने को मजबूर हो गया है।

बाल संरक्षण के मुद्दे पर हुई एकदिवसीय कार्यशाला

JAMSHEDPUR : सिदगोड़ा स्थित टाउन हॉल में बुधवार को मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत बाल संरक्षण के मुद्दे पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। इसमें मिशन वात्सल्य के स्पॉन्सरशिप योजना, फॉस्टर केयर योजना एवं बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में उपवििकास आयुक्त सह एडीएम अनिकेत सवान, एसडीएम धालभूम शताब्दी मजुमदार, रूरल एसपी ऋषभ गर्ग, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, सहायक निदेशक-सामाजिक सुरक्षा नेहा संजना खलखो, सभी बीडीओ व अन्य स्टैक होल्डर उपस्थित रहे।

अंडर-19 क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा प. सिंहभूम

CHAIBASA : साकेत कुमार सिंह की तूफानी पारी की बदौलत पश्चिमी सिंहभूम ने जमशेदपुर को एकरफरा मुकाबले में छह विकेट से पराजित कर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। अब फाइनल में पश्चिमी सिंहभूम का मुकाबला रांची से 7 फरवरी को रांची के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

झामुमो 28 फरवरी तक चलाएगा सदस्यता अभियान

CHAIBASA : झामुमो का विशेष सदस्यता अभियान 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें दो लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर बुधवार को चाईबासा में जिला संयोजक प्रमुख सोनाराम देवगम ने बैठक की। देवगम ने बताया कि अब तक पश्चिमी सिंहभूम जिला में 20 हजार नए सदस्य बन चुके हैं। इसके पश्चात प्रखंड व नगर समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। बैठक में इकबाल अहमद, सुभाष बनर्जी, राहुल आदित्य, दीपक कुमार प्रधान, अभिषेक सिंक्, दिनेश चंद्र महतो, जगमोहन महाराणा आदि उपस्थित थे।

सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब का 8 तक होगा निबंधन

GHATSILA : सिदो-कान्हू युवा खेल क्लब के निबंधन को लेकर बुधवार को घाटशिला प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक हुई। क्रीड़ा प्रकाष्ठ के प्रभारी सुशील माडों की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की अनुमति से इस क्लब का गठन किया गया है, लेकिन क्लब के सदस्यों द्वारा अभी तक इसका निबंधन नहीं कराया है। निबंधन होने पर सरकार से खेल के विकास के लिए हर साल 25 हजार रुपये मिलेंगे। निबंधन 8 फरवरी तक होगा।

जैविक खाद उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन आज

GHATSILA : चाकुलिया स्थित ध्यान फाउंडेशन की गौशाला में जैविक खाद उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन गुरुवार को होगा। गौशाला से प्रतिदिन निकलने वाले 100 टन गोबर से जैविक खाद बनाई जाएगी। क्षेत्र के किसानों को भी गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

केंद्रीय बजट प्रस्ताव व 4 श्रम कानूनों को बताया देशवासियों की मौत का वारंट

ट्रेड यूनियनों ने किया विरोध प्रदर्शन, फूँका केंद्र सरकार का पुतला

PHOTON NEWS JSR : केंद्रीय बजट प्रस्ताव 2025-26 के साथ-साथ चार श्रम संहिताओं को लागू करने की पहल के खिलाफ बुधवार को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच, कोल्हान प्रमंडल ने विरोध प्रदर्शन किया। बिरसा चौक, साकची में नुक्कड़ सभा के बाद बजट प्रस्ताव और 4 श्रम संहिताओं का पुतला फूँका गया। नुक्कड़ सभा में वक्ताओं ने एक स्वर में बजट प्रस्तावों की निंदा करते हुए इसे आम आदमी के साथ विश्वासघात और राष्ट्रीय संपत्ति की लूट का खाका बताया। इसके साथ ही श्रम संहिताओं को लागू करने की सरकार की बेताब पहल की निंदा की गई। कहा गया कि चारों श्रम संहिताएं



साकची गोलाचककर के पास प्रदर्शन करते यूनियनों के कार्यकर्ता

● फोटोन न्यूज

श्रमिकों के अधिकारों की मौत का वारंट होगा। यह भी कहा गया कि श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की घोषणा होने पर इसके विरोध में सभी उद्योगों

और क्षेत्रों के श्रमिक अखिल भारतीय हड़ताल पर जाएंगे। कार्यक्रम को बिनोद राय,अंबुज कुमार ठाकुर, बिश्वजीत देव, परविंदर सिंह सोहल, हीरा

अरकने, संजय कुमार, बिनोद राय, धनंजय शुक्ला आदि ने संबोधित किया वक्ताओं ने बताया , बजट प्रस्ताव एक ओर कारपोरेट घरानों को परमाणु

ऊर्जा और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर कब्जा करने का अवसर देगा, वहीं दूसरी ओर बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई के साथ ही खनन, बिजली तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सेवाओं के निजीकरण की गति को तेज करेगा। कारपोरेट के इशारे पर 'इजऑफ इंड्रेंज बिजनेस' के नाम पर बजट प्रस्ताव तो बनाए गए, लेकिन रोजगार सृजन और न्यूनतम मजदूरी के माध्यम से आम आदमी के लिए 'जीवनयापन में आसानी' सुनिश्चित करने के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई। कोल्हान के ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से मजदूरों-कर्मचारियों के सभी तबकों तथा आम जनता से अपील की गई

कि वे इस जनविरोधी, मजदूर-विरोधी तथा राष्ट्रविरोधी बजट प्रस्तावों का विरोध करें, साथ ही चारों श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन को रोकने के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार रहें। कार्यक्रम में मनोज कुमार सिंह, अंजनी कुमार, धनंजय शुक्ला, नागराजु, विक्रम कुमार, पीआर गुप्ता, हरिशंकर सिंह, सुशील कुमार सिंह, बेबी कुमारी, नवीन कुमार, मनीष कुमार, प्रिया महतो, सुशील कुमार, राजीव कुमार सिंह, सुब्रतो देव, रवि कुमार, आरएस राय, धनंजय शुक्ला, जफर खान, विक्रम कुमार, एन एस पाल, सरवन कुमार, यश विश्वकर्मा, शशि कुमार, जयशंकर प्रसाद उपस्थित थे।

JAMSHEDPUR : उपायुक्त अनन्य भित्तल के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू कर दी गयी है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत जिला के नौ सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीट पर अभिवांचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल rteastsinghbhum.com पर 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन

निम्नांकित दस्तावेज होंगे मान्य

- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रमाण के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख हो।
- 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड, असेसिक शल्य चिकित्सक, सदा अस्पताल/ चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- संबधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र।

भरा जा सकता है।

लॉटरी के माध्यम से होगा चयन

गौरतलब है कि विगत वर्ष उपायुक्त के निर्देशानुसार उपवििकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधीक्षक, शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं अभिभावक संघ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कुल चार चरणों में 1504 सीट के विरुद्ध 1384 बच्चों का लॉटरी के माध्यम चयन किया गया था, जो अभी तक के आरक्षित सीट पर सर्वाधिक नामांकन है।

प्रयागराज से पैदल जमशेदपुर पहुंची 70 वर्षीय महिला

अपने लोगों से बिछड़ गई थीं छायेानगर निवासी कांति देवी, 10 दिन में तय की 700 किलोमीटर की दूरी



छायेानगर स्थित अपने आवास पर कांति देवी

● फोटोन न्यूज

25 जनवरी से अपनी पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने दिन में लोगों से थोड़ा-बहुत खाना मांगा

और रात को जहां जगह मिली, वहीं सो गई। बिना किसी साधन के उन्होंने लगातार 10 दिनों तक

परिवार में दौड़ गई खुशी की लहर

कांति देवी के बिछड़ने की खबर से उनके परिवार में हड़कंप मच गया। परिवार के सदस्य अलग-अलग जगहों पर उनकी खोज में निकल पड़े। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कांति देवी पैदल ही घर लौटने का साहस करेंगी। 4 फरवरी को जब वे सुरक्षित अपने घर पहुंचीं, तो परिवार के लोग हैरान और भावुक हो गए।

चलते हुए 700 किलोमीटर का सफर तय किया। कांति देवी ने कभी पूजा-पाठ में

दो करोड़ का बकाया होने पर गोविंदपुर में जलापूर्ति हुई ठप

पहले भी तीन दिन तक नहीं हुई थी वाटर सप्लाई, लोग हुए परेशान

PHOTON NEWS JSR: गोविंदपुर जलापूर्ति योजना एक बार फिर विवादों में घिर गई है। जेमिनी इंटरप्राइजेज, जो इस योजना का संचालन कर रही है, ने पेयजल विभाग द्वारा पिछले 12 महीनों से पेमेंट न मिलने के कारण आज जलापूर्ति को वाट्सएप के माध्यम से नोटिस देकर बंद कर दिया। एजेंसी का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पर दो करोड़ रुपये का बकाया है। इस कारण गोविंदपुर क्षेत्र के 24 पंचायतों की लाखों की आबादी पानी के लिए तरस गई। इस मुद्दे पर जिला परिषद सदस्य डॉ. परितोष सिंह ने जानकारी दी और कहा कि गोविंदपुर जलापूर्ति योजना अपने प्रारंभिक दौर से ही विवादों का सामना कर रही है। कभी विभाग की लापरवाही तो कभी ठेकेदार की वजह से यह योजना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ रही है। हाल ही में भी तीन दिन तक जलापूर्ति बाधित रही थी और आज फिर



जलापूर्ति योजना के प्लांट में पहुंचे जिला परिषद के सदस्य डॉ. परितोष सिंह

● फोटोन न्यूज

लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

पानी की आपूर्ति में आई इस अव्यवस्था को लेकर लोग गुस्से में हैं। और यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया, तो जनता सड़को पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी।

फंड आने के बाद मिलेगा भुगतान

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालयक अभियंता सुनील कुमार का कहना है कि एजेंसी का जो भी बकाया है उसका बिल विभाग को भेज दिया गया है। विभाग से पैसा आने के बाद एजेंसी को भुगतान कर दिया जाएगा।

यही स्थिति उत्पन्न हुई है। डॉ. सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि प्रशासन और पेयजल

विभाग ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी में बड़ी आबादी पानी

की किल्लत से जूड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना शुरू से ही लूट-खसोट की योजना रही है।

बाइक की चपेट में आकर पांच छात्राएं हुई घायल



अस्पताल में इलाजरत घायल छात्रा ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS JSR : सीतारामडेरा चर्च के समीप स्कूल जा रहीं पांच छात्राओं को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे पांचों छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। आनन-फानन सभी को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां दो छात्राओं की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायल छात्राओं में अष्टमी कुमारी, शानू कुमारी, रश्मि कुमारी, सुरभि कुमारी और खुशी कुमारी शामिल

हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पांचों छात्राएं आदिवासी उच्च विद्यालय की छात्राएं हैं। सभी अपने घर से स्कूल के लिए रही थीं। इसी दौरान चर्च के समीप स्टैंट कर रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इसकी सूचना सीतारामडेरा थाना की पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल सभी का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है।

डंपर की चपेट में आकर युवक की मौत



POTKA : पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें डंपर की चपेट में आकर ओडिशा के एक युवक की मौत हो गई। घटना कोवाली-हल्दीपोखर मुख्य मार्ग पर हुई थी। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, ओडिशा के तिरिंग थाना क्षेत्र के मंगलडीह निवासी मंगल मुंडा बुधवार सुबह अपनी बाइक से जमशेदपुर जा रहा था। गंगाडीह मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और वह तेज रफ्तार से आ रही डंपर से टकरा गया। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए कोवाली थाना की पुलिस ने अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

CHAKRADHARPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत चक्रधरपुर रेल मंडल में बुधवार को विचित्र घटना हुई। यहां मालगाड़ी रेलवे ट्रैक से उत्तर कर पास की एक बस्ती में घुस गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। यह घटना ओडिशा की है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी की शॉटिंग की जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। सुबह करीब 6 बजे कंटेनर वाली मालगाड़ी शॉटिंग माल गोदाम शेड में शॉटिंग के दौरान पटरी से उतरकर सीधे माल गोदाम बस्ती में जा घुसी। ट्रेन के बस्ती में घुसते ही अफरातफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे और किसी तरह अपनी जान बचाई। लोगों का कहना है कि और 10 से 15 फुट भी अगर ट्रेन भीतर घुसती तो कई झोपड़ियों को अपनी



घटनास्थल पर लगी भीड़

● फोटोन न्यूज

रेलवे जीएम पहुंचे राउरकेला, लगाई फटकार

CHAKRADHARPUR : मालगाड़ी के बस्ती में घुस जाने के मामले को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने बेहद गंभीरता से लिया है। राउरकेला पहुंचे जीएम ने पत्रकारों से कहा कि यह घटना पूरी तरह से लापरवाही है। जिसकी भी लापरवाही से ट्रेन पटरी छोड़कर बस्ती में घुसी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जीएम बुधवार को अपने तब कार्यक्रम के तहत डंगुवापोशी सेक्शन के बोलांनी स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे।

चपेट में ले लेती। इससे कई लोगों कि मौत हो जाती। बहरहाल, एक बड़ी घटना टल गई। घटना के बाद शॉटिंग कर रहे चालक भी मौके से भाग निकले। बता दें कि जिस बस्ती में ट्रेन घुसी है वह बस्ती भी पूरी

तरह अवैध है। रेलवे की जमीन पर बसी इस अवैध बस्ती में रहने वालों को अब यह डर सताते लगा है कि रेलवे माल गोदाम बस्ती को खाली करने के लिए शायद अब इस तरह की हरकत कर रही है।

निजी विद्यालयों में नामांकन को आवेदन की प्रक्रिया शुरू

JAMSHEDPUR : उपायुक्त अनन्य भित्तल के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू कर दी गयी है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत जिला के नौ सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीट पर अभिवांचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल rteastsinghbhum.com पर 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन

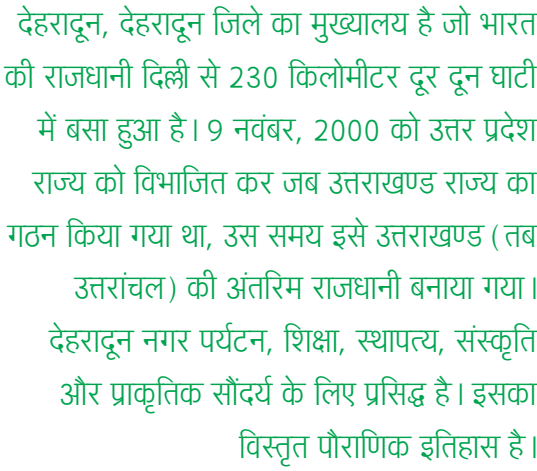
निम्नांकित दस्तावेज होंगे मान्य

- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रमाण के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख हो।
- 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड, असेसिक शल्य चिकित्सक, सदा अस्पताल/ चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- संबधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र।

भरा जा सकता है।

लॉटरी के माध्यम से होगा चयन

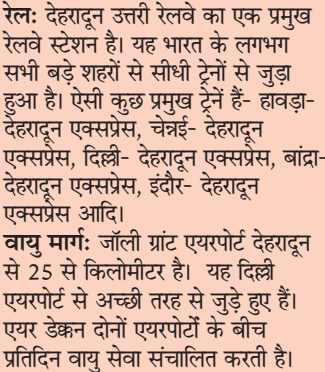
गौरतलब है कि विगत वर्ष उपायुक्त के निर्देशानुसार उपवििकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधीक्षक, शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं अभिभावक संघ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कुल चार चरणों में 1504 सीट के विरुद्ध 1384 बच्चों का लॉटरी के माध्यम चयन किया गया था, जो अभी तक के आरक्षित सीट पर सर्वाधिक नामांकन है।



सतौला देवी मंदिर - देहदहून से लगभग 15 कि.मी. दूर स्थित प्रसिद्ध सतौला देवी मंदिर पहुंचने के लिए बस द्वारा जैतावाला तक जाकर वहां से पंजाबीवाला तक 2 कि.मी. जीप या किसी हल्के वाहन द्वारा तथा पंजाबीवाला के बाद 2 कि.मी. तक पैदल रास्ते से मंदिर पहुंचा जा सकता है।

देहरादून

देहरादून का इतिहास कई सीं वर्ष पुराना है। देहरादून से 56 किलोमीटर दूर कालसी के पास स्थित शिलालेख से इस पर तीसरी सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का अधिकार होने की सूचना मिलती है। देहरादून ने सदा से ही आक्रमणकारियों को आकर्षित किया है। खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में 1654 में इस पर मुगल सेना ने आक्रमण किया था। सिसमोर के राजा सुभाक प्रकाश की सहायता से खान गढ़वां के राजा पृथ्वी शाह को हराने में सफल रहे। राजा से अपदस्थ किए गए राजा को इस शर्त पर गद्दी पर आसीन किया गया कि वे नियमित रूप से मुगल बादशाह शाहजहाँ को कर चुकाया करेंगे। इसे 1772 में गुज्जरों ने लूटा था। तत्कालीन राजा ललत शाह जो पृथ्वी शाह के वंशज थे, की पुत्री की शादी गुलाब सिंह नामक गुज्जर से की गई थी। गुलाब सिंह के पुत्र का नियंत्रण देहरादून पर था और उनके वंशज इस समय भी नगर में मिल सकते हैं। गढ़वाल के राजा ललत शाह के पुत्र प्रदुमन शाह के शासन काल में रोहिल्ला नजीब के पोते गुलाम कादिर के नेतृत्व में अफगानों का आक्रमण हुआ जिसमें उसने गुरु राम राय के अनुयायियों और शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया। जिन लोगों ने हिन्दू धर्म त्यागने का निर्णय लिया, उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन अन्य लोगों के साथ बहुत निर्भरतापूर्वक व्यवहार किया गया। सहारनपुर के राज्यपाल और अफगान प्रमुख नजीबुद्दौला भी देहरादून को अपने अधिकार में करने के उद्देश्य में सफल रहा उसके बाद देहरादून पर गुज्जरों, सिक्खों, राजपूतों और गोरखाओं के लगातार आक्रमण हुए और यह उज्जाड़ और सुंदर भूमि शीघ्र ही बंजर स्थल में बदल गई। 1783 में एक सिक्ख प्रमुख बुधेल सिंह ने देहरादून पर आक्रमण किया और बिना किसी बड़े प्रतिरोध के सहजता से इस क्षेत्र को जीत लिया। 1786 में देहरादून पर गुलाम कादिर का आक्रमण हुआ। उसने पहले हरिद्वार को लूटा और फिर देहरादून पर कहर बरपाया। उसने नगर पर आक्रमण किया और उसे जमकर लूटा। तथा बाद में देहरादून को बर्बाद कर दिया। 1801 तक अफगान सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा ने दून घाटी पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1814 में नालापानी के लिए अफगान सिंह थापा के पोते बालभद्र सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा और जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में ब्रिटिश के बीच युद्ध हुआ। गोरखाओं ने इस लड़ाई में जमकर बराबरी की और अपने समेत कई ब्रिटिश सेनाओं को जपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। इस बीच गोरखाओं को एक असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ा और उन्हें नालापानी के



जलवायु : देहरादून की जलवायु समशीतोष्ण है। यहां का तापमान 16 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है जहां शीत का तापमान 2 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। देहरादून में औसतन 2073.3 मिलीमीटर वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है। अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है।

नगर के विषय में: राजपुर मार्ग पर या डालनवाला के पुराने आवासिय क्षेत्र में पूर्वी यमुना नहर सड़क से देहरादून शुरु हो जाता है। सड़क के दोनों किनारे स्थित छोटे बरामदे और सुन्दर ढालदार छतों वाले छिटे बंगले इस शहर की पहचान हैं। इन बंगलों के फलों से लदे हुए पेड़ों वाले बगीचे बरस ध्यान आकर्षित करते हैं। घण्टाघर से आगे तक फैलाहुआ रंगीन पलटन बाजार यहाँ का सर्वाधिक पुराना और व्यस्त बाजार है। यह बाजार तब अस्तित्व में आया जब 1820 में ब्रिटिश सेना की टुकड़ी को आने की आवश्यकता पड़ी। आज इस बाजार में फल, सब्जियां, सभी प्रकार के कपड़े, तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेंट्स) जुते और घर में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुयें मिलती हैं। इसके स्टोर माल, राजपुर सड़क तक है जिसके दोनों ओर विश्व के लोकप्रिय उत्पादों के शो रूम हैं। अनेक

देहरादून देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और यहां पर किसी भी जगह से यातायात सेवा से आसानी से जुड़ा हुआ जा सकता है। सभी तरह की बसें, (साधारण और लक्जरी) गांधी बस स्टैंड (जो दिल्ली बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है), यहां से खुलती हैं। यहां पर दो बस स्टैंड हैं। देहरादून और दिल्ली, शिमला और मसूरी के बीच डिलक्स/सेमी डिलक्स बस सेवा उपलब्ध है। ये बसें अंतर्देशीय टाउन के नजदीक स्थित अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनस से चलती हैं। दिल्ली के गांधी रोड बस स्टैंड से एसी डिलक्स बसें (टोलो) भी चलती हैं। यह सेवा हाल में ही यूएसएसआरटीसी द्वारा शुरू की गई है। आईएसबीटी, देहरादून से मसूरी के लिए हर 15 से 70 मिनट के अंतराल पर बसें चलती हैं। इस सेवा का संचालन यूएसएसआरटीसी द्वारा किया जाता है। देहरादून और उसके पड़ोसी जिलों के बीच भी नियमित रूप से बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

रहे हैं तथा कुछ नगर के चारों ओर केन्द्र हैं। देहादून राणील रेड्चेशायर अंतराष्ट्रीय केन्द्र है। रिसना ब्रिज शायर गृह डालनवाला में हैं। जो मानसिक चुनौतियों के लिए कार्य करते हैं। मानसिक चुनौतियों के लिए काम करने के अतिरिक्त राणील रेड्चेशायर अंतराष्ट्रीय केन्द्र ने टी.वी व अधग्रह के इलाज के लिये भी अस्पताल बनाया। अधिकशः संस्थायें भारत और विदेश से स्वेच्छ से आने वाले को आकर्षित तथा प्रोत्साहित करती हैं। आवश्यकता विहीन काम कहना है कि स्वेच्छ से काम करने वाले इन संस्थायों को ठीक प्रकार से चलाते हैं। तथा अयोग्य, मानसिक चुनौतियों और कम योग्य वाले लोगों को व्यक्तिगत रूप से चेवना देते हैं। देहादून अपनी पहचानों और बतानों के साथ-साथ सांस्कृतिक का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। चारों ओर पर्वतों और हरियाली से घिरा होने के कारण यहाँ सांस्कृतिक करना बहुत सुखद है। लौची देहादून का पर्यायवाची है क्योंकि यह स्वादिष्ट फल चुनिंदा जलवायु में ही उगता है। देहादून देश की उन जगहों में से एक है जहाँ लौची उगती है। लौची के अतिरिक्त देहादून की चारों ओर बेर, नाशपत्ती, अमरुद और आम के पेड़ हैं। जो नगर की बनावट को घेरे हयें हैं। ये



सारी चीजें घाटी के आकर्षण में वृद्धि करती है। यदि मई माह या जून के शुरू की गर्मियों में भ्रमण के लिये जाएं तो तुम इन फलों को केवल देखेंगे ही नहीं बल्कि खरीदेंगे भी। बासमती चावल की लोकप्रियता देहरादून या भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। एक समय अंग्रेज भी देहरादून में रहते थे और वे नगर पर अपना प्रभाव छोड़ गये। उदाहरण के रूप में देहरादून की बैकरीज (बिस्कुट आदि) आज भी यहाँ प्रसिद्ध है। उस समय के अंग्रेजों ने यहाँ के स्थानीय स्टाफ को सेंकना सिखाया। यह निपुणता बहुत अच्छी सिद्ध हुई तथा यह निपुणता अगली संतति सन्तान में भी आयी। फिर भी देहरादून के रहने वालों के लिये यहाँ के स्थानीय रस्क, केक, होट क्रोस बन्स, पेस्टिज और कुकीज मित्रों के लिये सामान्य उपहार है, कोई भी ऐसी नहीं बनाता जैसा देहरादून में बनती है। दूसरा उपहार जो पर्यटक यहाँ से ले जाते हैं विख्यात कालांटी की टॉफी जोकि कालांटी रेस्पोंडेंट (गुणवत्ता वाली दुकानों) से मिलती हैं। यद्यपि आज बड़ी संख्या में दूसरी दुकानों (स्टोर) से भी ये टॉफी मिलती है परन्तु असली टॉफी आज भी सर्वोत्तम है। देहरादून में आनंद के और बहुत से पर्याप्त विकल्प हैं।

राहुल गांधी की देश-विरोधी बचकानी राजनीति



ललित गर्ग

राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने अन्य सांसदों की ही तरह देश की अखंडता और एकता की रक्षा करने की शपथ ली थी, लेकिन उनके द्वारा समय-समय पर दिये गये वक्तव्य एवं टिप्पणियां पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की राह पर अग्रसर हैं और उनका इरादा भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नष्ट करना और देश को गृहयुद्ध की ओर धकेलना है।

एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नीचा दिखाने के इरादे से ऐसा बयान दिया है जो भारत की साख को आघात लगाने वाला है बल्कि देश की एकता एवं अखण्डता को ध्वस्त करने वाला है। राहुल गांधी किस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान देने में माहिर हो गए हैं, यह इस कथन से फिर सिद्ध हुआ कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर इसलिए बार-बार अमेरिका जा रहे थे, ताकि भारतीय प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए। राहुल गांधी मोदी-विरोध में कुछ भी बोले, यह राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वे मोदी विरोध के चलते देश-विरोध में जिस तरह के अनाप-शनाप दावे करते हुए गलत बयान देते हैं, वह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता एवं बचकानेपन को ही दर्शाता है। आखिर कब राहुल एक जिम्मेदार एवं विवेकवान प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राजनीति से हटकर भी गहरे व्यक्तिगत आत्मीय मित्रवत संबंध है, इसलिये उनका शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने पर किसी तरह का संदेह नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को लेकर राहुल के बयान पर हैरानी होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि लोकसभा में संसदीय कार्यमंत्री किशन रिंजजू ने राहुल गांधी की इस विचित्र बात पर आपत्ति जताई, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि वह ऐसी बात कहकर भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन ऐसे झूठे, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले बयान से भारत की छवि को गहरा नुकसान हुआ है। यह तय है कि विदेशी मंत्री के प्रतिवाद का राहुल गांधी की संहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसी मिथ्या बातें करके वे प्रधानमंत्री पर हमला करने का कोई अवसर नहीं चुकते। वह प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी को कोई महत्व नहीं देते। आखिर यह किसी से छिपा नहीं कि वह उनके खिलाफ तू-तड़ाक सफल अशालीन एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग करते रहे हैं। विडंबना यह है कि इस आदत का परित्याग वह नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। समस्या केवल यह नहीं कि वह प्रधानमंत्री पद की गरिमा को परवाह नहीं करते। समस्या यह भी है कि वह प्रायः ऐसी बचकानी बातें कर जाते हैं, जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होती हैं या दूसरे देशों से संबंधों पर बुरा असर डालती हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने अन्य सांसदों की



ही तरह देश की अखंडता और एकता की रक्षा करने की शपथ ली थी, लेकिन उनके द्वारा समय-समय पर दिये गये वक्तव्य एवं टिप्पणियां पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की राह पर अग्रसर हैं और उनका इरादा भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को नष्ट करना और देश को गृहयुद्ध की ओर धकेलना है। इस तरह राहुल गांधी द्वारा देश में विभाजन के बीज बोने के प्रयास निंदनीय ही नहीं, घोर चिन्तनीय है। सत्ता के लालच में कांग्रेस एवं उनके नेता देश की अखंडता के साथ समझौता और आम आदमी के भरोसे को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि भारत से है। राहुल गांधी अक्सर भारत राष्ट्र अर्थात भारत के संविधान यानी आंबेडकर के संविधान के खिलाफ विषमवन करते दिखाई देते हैं। गांधी परिवार की हार्मुह में राम और बगल में छुरीह वाली कहावत जनता के सामने बार-बार आती रही है। आंबेडकर के अस्तित्व को नकार कर भारत के संविधान को बदलने के बाद गांधी परिवार देश का विभाजन, दुश्मन देश के नेताओं एवं शक्तियों के सपनों का टुकड़ों वाला भारत चाहता है। आखिर राहुल गांधी और कांग्रेसी किस बात के लिए संविधान की प्रति लेकर चलते हैं? इस तरह एक गैर जिम्मेदार और बचकाने नेता का लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होना क्या देश का दुर्भाग्य नहीं है? राहुल गांधी को गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। राहुल गांधी अपने आधे-अधूरे, तथ्यहीन एवं विध्वंसात्मक बयानों को लेकर निरन्तर चर्चा में रहते हैं। उनके बयान

हास्यास्पद होने के साथ उद्देश्यहीन एवं उच्छृंखल भी होते हैं। राहुल ने पहले भी बातों-बातों में यह कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वह देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं। सरकार की नीतियों से नाराज होना, सरकार के कदमों पर सवाल उठाना उनके लिए जरूरी है। राजनीतिक रूप से यह उनका कर्तव्य भी है। लेकिन चीन के साथ उनकी सहानुभूति अनेक प्रश्नों को खड़ा करती है। ऐसे ही सवालों में आज तक इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? वह यह नहीं बताते कि 2008 में अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान सोनिया गांधी और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता क्यों किया था? इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी राफेल विमान सौदे में कथित दलाली खोज लाए थे, तो यहां तक कह गए थे कि खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें बताया था कि दोनों देशों में ऐसा कोई समझौता नहीं, जो राफेल विमान की कीमत बताने से रोकता हो। उनके इस झूठ का खंडन फ्रांस की सरकार को करना पड़ा था। डोकलाम विवाद के समय वह भारतीय विदेश मंत्रालय को सूचित किए बिना किस तरह चीनी राजदूत से मुलाकात करने चले गए थे। जब इस मुलाकात की बात सार्वजनिक हो गई तो उन्होंने यह विचित्र दावा किया कि वह वस्तुस्थिति जानने के लिए चीनी राजदूत से मिले थे। क्या इससे अधिक गैरजिम्मेदाराना हरकत और कोई हो सकती है? राहुल गांधी के गैरजिम्मेदाराना बयानों से यही पता चलता है कि उन्हें न तो प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन है, न रक्षा मंत्री की और न ही विदेश मंत्री की। यह भी स्पष्ट है कि

उन्हें शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं। ध्यान रहे, वह सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर भी बतूके सवाल खड़े कर चुके हैं। उनकी कार्यशैली एवं बयानबाजी में अभी भी बचकानापन एवं गैरजिम्मेदाराना भाव ही झलकता है। लगता है कांग्रेस के शीर्ष नेता एवं प्रतिपक्ष के नेता होने के कारण वे अहंकार के शिखर पर चढ़ बैठे हैं, निश्चित ही राहुल के विष-बुझे बयान इसी राजनीतिक अहंकार से उपजे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन राष्ट्र की वे तरफदारी करते एवं चीन के एजेंडे को बल देते नजर आते हैं। उनका यह रवैया नया नहीं, लेकिन यह देश के लिये घातक है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले की राहुल गांधी की अनावश्यक आलोचना को पाकिस्तान ने अपने पक्ष में भुनाने का काम किया था। अब भी वह सीमा विवाद पर चीन की बातों को अहमियत देते हैं और भारत सरकार की जानकारी पर यकीन नहीं करते। जनता यह गहराई से देख रही है कि राहुल किस तरह गलवान में हमारे सैनिकों की वीरता-शीर्य-बलिदान पर सवाल उठाते रहे हैं, भारत की बढ़ती साख, सुरक्षा एवं विकास की तस्वीर को बड़ा लगा रहे है। यह समझ आता है कि वह घरेलू मुद्दों पर सरकार को घेरें और उसकी आलोचना करें, लेकिन कम से कम ऐसी निराधार और मगमगूत बातें तो न करें, जिससे प्रधानमंत्री पद का उपहास उड़े, देश हित आहत हो। उल्लेखनीय बात यह है कि निन्दक एवं आलोचक कांग्रेस को सब कुछ गलत ही गलत दिखाई दे रहा है। मोदी एवं भाजपा में कहीं आहत भी हो जाती है तो कांग्रेस में भूकम्प-सा आ जाता है। मजे की बात तो यह है कि इन कांग्रेसी नेताओं को मोदी सरकार की एक भी विशेषता दिखाई नहीं देती, कितने ही कीर्तिमान स्थापित हुए हो, कितने ही आयाम उद्घाटित हुए हो, कितना ही देश को दुश्मनों से बचाया हो, कितनी ही सीमाओं एवं भारत भूमि की रक्षा की हो, कितना ही आतंकवाद पर नियंत्रण बनाया हो, कितनी ही देश के तरक्की की नई इबारतें लिखी गयी हो, समूची दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही हो, लेकिन इन राहुल एवं कांग्रेसी नेताओं को सब काला ही काला दिखाई दे रहा है। कमियों को देखने के लिये सहसाक्ष बनने वाले राहुल अच्छाई को देखने के लिये एकाक्ष भी नहीं बन सके हैं। (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

राहुल का चीन गान

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अद्भुत नेता हैं उनके वक्तव्य में समझ और संयम को अलग कर दें तो सब कुछ होता है। संसद में राष्ट्रपति के अभी भाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने भरपूर आत्मविश्वास दिखाया और भरपूर आक्रामकता भी दिखाई। लेकिन उनके भाषण की विषय-वस्तु हमेशा की तरह अटपटी और अलबेली रही। उनके बारे में यह एक स्थापित तथ्य है कि भारती या विदेश में जहां कहीं मोदी या मोदी सरकार के विरुद्ध कुछ घटित होगा या कुछ बोला जाएगा या जहां से भी मोदी को कोई चुनौती मिल रही होगी, चाहे वह देश से हो या विदेश से, राहुल उसके पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। प्रायः उनके भाषण में मोदी विरोध या देश विरोध के बीच की रेखा धुंधली होती है। उन्होंने राष्ट्रपति के समूचे अभिभाषण को पुनरावृत्ति बताते हुए हर मोर्चे पर मोदी सरकार की विफलता को रेखांकित किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ-ग्रहण समारोह के मामले में यह आरोप भी लगाया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कई बार अमेरिका जाकर मोदी के लिए निर्भर जुटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इस पर विदेश मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे निहायत ही झूठा आरोप बताया और कहा कि उनकी टिप्पणी भारत की छवि खराब करने वाली है। अन्य बातों के अलावा राहुल गांधी के भाषण का एक मुख्य मुद्दा चीन और भारत की तुलना थी जिसमें चीन भारत से कई वर्ष आगे है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी विनिर्माण क्षमता से भारत को घेर रहा है। यानी वह अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता से भारत के बाजार पर और अपनी सैन्य क्षमता से भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। चीन जैसी क्षमता हासिल करने की कोशिश न करने के लिए उन्होंने न केवल एनडीए सरकार को दोषी ठहराया बल्कि अपनी यूपीए सरकार की भी आलोचना की। अब राहुल गांधी को यह कौन समझाए कि चीन की प्रौद्योगिकी या सैन्य क्षमता हो वह उसकी राज्य व्यवस्था का परिणाम है जिसमें ना तो भारत जैसे लोकतंत्र को ही जगह है और न अधिकचरे विचारों वाले किसी नेता के लिए कोई स्थान है।

चिंतन-मनन

विचार-निर्विचार, चिंतन-अचिंतन

पूरा विश्व, विचारों पर चलता है, सारे आविष्कार, युद्ध, आतंकवाद, साहित्य सृजन, भाषण, प्रवचन, तू-तू, मैं-मैं सब विचारों की देन है। विचार ही सब कार्यों को अंजाम देता है। भक्ति, प्रार्थना, व्यवहार, सेवा सब विचारों की देन है। हम सोचते हैं तो करते हैं होता है। अब प्रश्न यह है कि विचार कैसे हो, दो श्रेणियों में बांटा गया है उन्हें, सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मकता निर्माण करती है, नकारात्मकता विध्वंस, मनुष्य ने सभ्यता को ऊंचाई तक पहुंचाया है एक तरफ तो दूसरी तरफ नृशंसा के गर्त में भी। जैसे विचार वैसा वातावरण और वृत्त। विचार करना सुविचार करना कोई किसी को जबरदस्ती नहीं सीखा सकता क्योंकि संस्कार, लालन-पालन, शिक्षा, मनन-चिंतन, संगति, वातावरण से विचारों में परिवर्तन होता है। पता नहीं यह दुनिया कब से बनी है, मनुष्य ने सोचना कब से शुरू किया, उसमें कैसे-कैसे परिवर्तन होते गया यह एक बड़ा गूढ़ विषय है। इस पर शास्त्र रचे जा सकते हैं। विचारों ने ही तो इतना ज्ञान इस विश्व को दिया है विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, राजनीति, धर्म, कानून, जैसे-जैसे आवश्यकताएं होती गई या बढ़ती गई सब आविष्कार या रचना होती गई। आतंकवाद, विस्तारवाद, युद्ध भी विचारों का खेल है। नेतृत्व के गलत विचारों का खामियाजा पूरे देश को देना होता है, कौम हो देना होता है। धार्मिक उन्माद भी कुछ गलत विचारों की देन है। बुद्धिहीन या कम बुद्धि वाले लोगों को बुद्धिमान चालाक लोग भेड़ों की तरह हांक कर अपने ढंग से उपयोग या दुष्प्रयोग करते हैं। इन्सान का अपना वजूद जब कमजोर होता है तो वह हिम्पेटाइन हो जाता है दूसरों से और पीछे-पीछे चलने लगता है, उसे पता नहीं होता कि वह कुएं में जाएगा या खाई में। हर कर्म के पीछे विचार होता है। सत्कर्म और बुरे कर्म। बिना विचारों कोई कुछ नहीं करता, यह अलग बात है कि कितनी गहराई और गंभीरता से विचार किया जाता है। आदमी हमेशा विचारों के हिंडोले में हिचकोले खाता रहता है, कभी आनंददायक कभी दुख देने वाले विचारों से स्वास्थ्य, विचार से रोग, वीरोचित कार्य कायराना कार्य। इसलिए विचारों को सुधार लीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैंडकल ईशान और रिसर्च में भी यही पाया गया है कि रोग विचारों की देन है नकारात्मक विचारों की। सकारात्मक विचारों से, आशा, विश्वास से लोग निराग होते देखे गए हैं। गीता में कहा गया है चित्त बुद्धि निरोध की स्थिति में आना याने सब दृष्टि से संतुलन, शांति, आनंद, निर्भयता में जीना। अति प्रसन्न और अति दुःखी होना भी गलत है। हमेशा समस्थिति में रहना। भगवान विष्णु की तरह जो शेष नाग की शैया पर (विषमता) में भी शांत और प्रसन्न रहते हैं हमें हमारे पौराणिक दृष्टांतों से बहुत कुछ हासिल हो सकता है पर हम पड़े सोचे और चलें तब। सोचिए आपको कैसे जीना है।



नरेन्द्र भारती

देश में प्रतिदिन खून से सड़कें लाल हो रही हैं अक्सर देखा गया है की लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और बेमौत मरते रहते हैं 'वैशक प्रतिवर्ष की तरह 11 जनवरी2025से 17 जनवरी 2025 तक पूरे भारतभर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया ऐसे आयोजनों प? करोड़ों रुपया खर्च किया गया सेमिनार लगाए गए और कार्यक्रम किये गए ' यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया गया लेकिन सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं ' सड़क हादसे अभिशाप जितने जा रहे हैं 'मानव जीवन अनमोल है देश के नागरिको को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सड़क हादसों पर रोक लग सके।सड़क सुरक्षा के ऐसे आयोजन औपचारिकता भर रह गए हैं। प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपया बहाया जाता है मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात ही निकलता है अगर सही तरीके से पैसा खर्चा किया जाए तो इन हादसो पर विराम लग सकता है मगर ऐसा नहीं हो रहा है। हर वर्ष लाखों लोग मारे जा रहे है। प्रतिवर्ष डेढ लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते है।नवम्बर 2025 के पहले सप्ताह से ही लोग सड़क हादसों में मारे जा रहे है देश में हर रोज इतने भीषण हादसे हो रहे है कि पूरे के पूरे परिवार मौत की नींद सो रहे हैं।कोहरे के कारण हजारों सड़क हादसे हो रहे है प्रतिदिन लोग मारे जा रहे है।यातायात के नियमों का पालन न करने पर ही इन हादसों में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्योंकि प्रशासन द्वारा लोगों को इन सात दिनों में यातायात नियमों के बारे में बताया जाता है फिर पूरा वर्ष लोग अपनी मनमानी करते है और



संजीव दाब्रु

आजादी के बाद से भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई है। अक्सर सामाजिक क्षेत्र में समस्याओं ने अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर प्रगति पर अवरोध खड़े किए हैं। देश की सामाजिक विषमताओं ने समाज में कई समस्याओं को पैदा किया है एवं आर्थिक प्रगति पर विभिन्न सोपानों में लगाम लगाई है। भारतीय समाज में विषमता एवं विविधता भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी है। स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में विषमताएं भारत के लिए चुनौती बनकर वर्तमान में कई बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आज जातिगत संघर्ष बढ़ गए हैं, जातिगत संघर्षों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बहुत जटिल बना दिया है।

यातयात नियमों का उल्लंघन करते है और मौत के मुंह में समाते जा रहे है।हालपरवाही से सड़कें रक्तर्जित हो रही है।चिराग बूझ रहें हैं।बच्चें अनाथ हो रहे हैं। आज युवा लापरवाही के कारण जान गंवा रहे है।युवा देश के कर्णधार है जो देश का भविष्य है।प्रतिवर्ष लाखों युवा हादसों में बेमौत मारे जा रहे है।इकलौतै चिराग अस्त हो रहे है।कोखें उजड़ रही है।माताओं प बहनों का सिंदूर मिट रहर हैं।बच्चें अनाथ हो रहे है।युवाओं को जागरूक करना होगा क्योंकि युवा ही विकराल हो रही सड़क हादसों की समस्या को रोक सकते है। लॉकडाउन में सड़क हादसों पर लगाम लग गई थी। सड़क सुरक्षा सप्ताह पर लाखों रुपया बहाया जाता है मगर फिर भी सुधार नहीं होता।जब तक लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे तब तक इन हादसों में लोग बेमौत मरतें रहेंगें। देश में जब 22 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था तब हादसे पूरी तरह रुक गए थे।लॉकडाउन के खुलते ही सड़क हादसों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई।कोरोना महामारी में हादसे कम हो गए थे।लॉकडाउन में जगली जानवर सड़को पर विचरण करते थे।परिवहन पूरी तरह बंद था।प्रदूषण भी शून्य हो गया था।साल 2020 के अप्रैल व मई माह में यातायात के साधन बंद हो गए थे।जून माह में ज्यों ही लॉकडाउन खुल गया था तो फिर से करोड़ों वाहन सड़को पर दौड़ पड़े।जनवरी 2025 से ही सड़क हादसों की रफ्तार बढ़ती जा रही है । साल 2024 में भी सड़क हादसों का सिलसिला पूरी साल अनवरत चलता रहा था और लोग लाखो लोग हादसों का शिकार होते रहे थे। देश के सैकड़ों सैनिक भी सड़क हादसों में शहीद हो गए थे।हजारों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। प्रतिदिन ही रही दुर्घटनाओं में हजारों लोग अर्पण हो गए जो ताउम्र हादसों का दर्श झेलते रहेंगें। देश में हर चार मिन्ट में एक व्यक्ति सड़क हादसे में मारा जाता है। प्रतिदिन देश की सड़कें रक्तर्जित हो रही है नौजवानों से लेकर बुजुर्ग काल का ग्रास बन रहे हैं। आंकड़ें बताते है कि सड़क दुर्घटनाओं में भारत अन्य देशों से शीर्ष पर हैं। शराब पीकर वाहन चलाना तथा चलते वाहनों में मोबाइल का प्रयोग ही हादसों का मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके कारण ही लाखो

लोग सड़क हादसों में मौत का शिकार हुए।2025 में भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं तथा प्रतिदिन दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है इसे सरकारों की लापरवाही की संज्ञा देना गलत नहीं होगा। ज्यादातर सड़क हादसे सदियों में होते है। लापरवाही के कारण हजारों सड़क हादसे हो रहे है सड़क हादसे अभिशाप बनते जा रहे हैं। दुष्ट के कारण आपसी टक्कर में दुर्घटनाएं होती हैं। देश के प्रत्येक राज्यों में हादसों की दर बढ़ती जा रही है दुर्घटना के बाद मुआवजे की राशि बांटने में व समाचार पत्रों में सुखियों में रहने में प्रशासन व नेता लोग आगे रहते हैं नेताओं द्वारा घड़ियाली आंसू बहाए जातें है।सड़क हादसों को रोकने के लिए एक नीति बनानी होगी।जागरूकता अभियान चलाने होंगें।देश की सड़को पर लाशों के चिथड़े बिखर रहे हैं। पंजाब, दिल्ली व उत्तरप्रदेश व हिमाचल प्रदेश में धूंध के कारण दर्जनों हादसों में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। मगर राज्यों की सरकारों को इससे कोई सरोकार नहीं है। देश के प्रत्येक राज्यों में हादसों की दर बढ़ती जा रही है दुर्घटना के बाद मुआवजे की राशि बांटने में व समाचार पत्रों में सुखियों में रहने में प्रशासन व नेता लोग आगे रहते हैं नेताओं द्वारा घड़ियाली आंसू बहाए जातें है।सड़क हादसों को रोकने के लिए एक नीति बनानी होगी।जागरूकता अभियान चलाने होंगें। सरकारों को लोगों को यातयात नियमों से संबधित शिपिरों का आयोजन करना चाहिए।आज करोड़ों के हिसाब से वाहन पंजीकृत है मगर सही ढंग से वाहन चलाने वालो की संख्या कम है क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को यातयात के नियमों का ज्ञान तक नहीं होता।पुलिस प्रशासन चालान इस्कात अपना कर्तव्य निभा रहे है मगर चालान इसका हल नहीं है इसका स्थायी समाधान ढूँडना होगा। बिना हेलमेट के नाबालिग से लेकर अघेड़ उम्र के लोग वाहनो को हवा में चलाते है और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जानबूझकर व नशे की हालत में दुर्घटना करने वाले चालकों के लाईसेंस रद्द करने चाहिए। ज्यादातर हादसे में नाबालिग चालक ही मारे जाते हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण भी इसमें साफ झलकती है

आज ज्यादातर युवा व लोग शराब पीकर व अन्य प्रकार का नशा करके वाहन चलाते है नतीजन खुद ही मौत को दावत देते हैं भले ही पुलिस यन्त्रों के माध्यम से शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिर्काज कस रही है मगर फिर भी लोग नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राज्यों की सरकारों द्वारा पुलिस को दी गई हार्डवे पैट्रोलिंग की गाड़ियां भी यातायात को कम करने में नाकाम साबित हो रही हैं।बढती सड़क दुर्घटनाओं के अनेक कारण है सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि 80 प्रतिशत हादसे मानवीय लापरवाही के कारण होते हैं।हापरवाह लोग सीट बेल्ट तक नहीं लगाते और तेज रफतार में वाहन चलाते हैं।देश में सड़क हादसों में स्कूली बच्चों के मारे जाने के हादसे भी समय-समय पर होते रहते हैं मगर कुछ दिनांक के रखा जाता है फिर वही परिपाटी चलती रहती है।जबकि होना तो यह चाहिए कि इन लापरवाह चालको को सजा देनी चाहिए ताकि मासूम बेमोत न मारे जा सके। अक्सर देखा गया है कि वाहन चालकों के पास प्राथमिक चिकित्सा बाक्स तक नहीं होतें ताकि आपातकालिन स्थिती में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा सके। प्रत्येक साल नवरात्रों में श्रध्दालू मंदिरों में ट्रको में जाते है और गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तथा मारे जाते हैं। आबरलौंडिंग से भी ज्यादातर हादसे होते हैं।सरकार को इन हादसों से सबक लेना चाहिए और व्यवस्था की खामियों को दूर करना चाहिए। सरकारों को अपना दायित्व निभाना चाहिए ताकि सड़क हादसों पर पूरी तरह रोक लग सके। सड़क हादसे अभिशाप बनते जा रहे हैं।ब्वेलगाम हो रहे यातायात पर लगाम लगाना सरकार व प्रशासन का कर्तव्य है लोगों को भी इसमें सहयोग करना होगा तभी इस समस्या का स्थायी हल हो सकता है यदि लोग सही तरीके से यातायात नियमों का पालन करते है तो सड़को पर हो रहे मौत के तांडव को रोक जा सकता है।कैन्डक सरकार को इस पर गौर करना होगा तथा देश में बढ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिए कारगर कदम उठाने होंगें नही तो देश के प्रत्येक महानगरों व शहरों से लेकर गांवों तक हर रोज लाशें बिछती रहेगी लोग मरते रहेंगें।

मुद्दा: धार्मिक-सामाजिक संघर्ष की विद्रूपताएं

को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं देश पर हिन्दी थोपे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया गया। आज भी विभिन्न राज्यों में भाषाई विवाद एक ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, चाहे वह बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी भाषाई विवाद अलग-अलग स्तर पर सतह पर पाए गए हैं। समान सिविल संहिता को लेकर बहुसंख्यक संविधान में आक्रोश है दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए डरा हुआ है कि कहीं उसकी अपनी अस्मिता एवं पहचान अस्तित्वहीन ना हो जाए। स्वतंत्रता के बाद से यह विकास की मूल धारणा थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ग विहीन समाज में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से समाज का आर्थिक विकास तथा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। पर स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्ग विभेद भाषाई विवाद ने अभी भी आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न की है। संविधान में संदेव सकारात्मक वर्ग विभेद एवं विकास की अवधारणा को प्रमुखता से शामिल किया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में भी विकास को वर्ग विभेद से अलग रखकर विकास की अवधारणा को बलवती बनाया गया है। सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विविधता वाले समाज को विवादों से परे रख आर्थिक विकास की परिकल्पना एक कठिन और दुष्कर अभियान जरूर है

पर असंभव नहीं है। और इसी की परिकल्पना को लेकर आजादी के पश्चात से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव सरकार ने समय-समय पर लापू किया है। विकास की अवधारणा में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के पिछड़े वर्ग को शामिल कर उन्हें समुख लाना होगा। यदि देश के पिछड़ा वर्ग और गरीब तबका विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद जैसे संकट अस्तित्वहीन हो जाएं और ऐसी समस्या धीरे-धीरे खत्म होती जाएगी। आवश्यकता यह है कि हमें राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर इस पर अमल करना होगा। फिर चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या समावेशी राष्ट्रवाद हो। समाज की मुख्यधारा में राष्ट्रवाद को एक प्रमुख अस्त्र बनाकर देश की प्रगति में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आजादी के 76 वर्ष बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, संप्रदायिकता, भाषावाद एवं क्षेत्रीय विघटनकारी प्रवृत्तियां सिर उठाये घूम रही हैं और हम इन पर अभी तक प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। हमें इन सब विसंगतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नगरिकता एवं भारत राष्ट्र की विकास की अवधारणा को राष्ट्रवाद से जोड़कर आर्थिक विकास को एक नया आयाम देना होगा, तब जाकर भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बन सकेगा।

Trump’s migrant crackdown sparks trade wars

Four days after his second inauguration, US President Donald Trump signed the Laken Riley Act. It provides for the arrest, detention and deportation of illegal immigrants charged with minor crimes, such as minor theft, shoplifting, assault or bodily injuries to another person, without waiting for a conviction by a legal court. The signing of this Bill reflects the hardening of sentiments among certain sections of the American people whose votes had steered Trump to victory in the recent presidential elections.

Among the measures that Trump has taken to crack down on the undocumented migrants in the US is the provision of military aircraft to deport thousands of arrested migrants. Additionally, 1,500 troops have been deployed on the US-Mexico border to monitor the incoming illegal migrants and install barriers to stop them.

Also, the entry of undocumented migrants to the US has been suspended, their right to seek asylum tightened and the powers of the Immigration and Customs Enforcement personnel to arrest and detain the illegal migrants on the US soil expanded. On February 1, Trump imposed 25 per cent tariffs on imports from Canada (10 per cent tariffs on import of Canadian Energy) and Mexico, citing national security concerns due to illegal immigration and drug trafficking, particularly of fentanyl. The accusations against Mexico are that its government provides safe havens to powerful drug cartels involved in the manufacture and transportation of dangerous narcotics. The Chinese goods will face 10 per cent tariffs as "China allows the transnational criminal organisations to engage in money-laundering activities which finance the drug trafficking networks." The Trump administration has said that unrestricted access to the US market is a privilege and leveraging tariffs is a powerful tool it would use to compel foreign governments to take stronger actions against illegal immigration and drug trafficking. Canada, Mexico and China have stated that their governments have taken meaningful actions to stop illegal migration and drug trafficking and they are willing to discuss further coordinated actions with the US government. Canadian PM Justin Trudeau has announced retaliatory tariffs of 25 per cent tariffs on US imports worth \$30 billion immediately and \$130 billion in 21 days. Mexican President Claudia Sheinbaum has ordered her Economy Minister to implement tariff and non-tariff measures against the US to defend her country's interests. She has denied the slander made by Washington that her government was working in an alliance with the drug trafficker cartels. She clarified that they had seized 20 million doses of fentanyl and detained one lakh persons tied to drug trafficking.

China has deplored the US tariffs and said that it would take necessary countermeasures, including complaining to the WTO against the wrong US practices. While Trump's policies primarily target illegal immigrants from Canada, Mexico and Central American countries, there are reportedly about 7,25,000 undocumented Indians in the USA, mainly from Punjab and Gujarat, and the Indians comprised about 3 per cent of all illegal border crossings in the US in 2024. The Indian government has clarified that it does not support illegal immigration anywhere and it would accept any illegal immigrants proven to be Indians. After a phone call with PM Modi on January 27, 2025, Trump said India would do "what is right on the deportation of the illegal immigrants." On the issue of H1B visas, there are differing views among Trump's core supporters. While the big business represented by Tesla owner and important Trump supporter Elon Musk favours the continuation of the H1B programme as it fosters innovation and excellence, others like Steve Bannon oppose it as it takes away jobs from the Americans. As the highly qualified foreign immigrants bring rich skills which are different from those of the natives and help create new businesses, jobs and increased consumption, the Trump administration is yet to order any major change in this programme.

Defence budget grows, but combat deficiencies persist

What is even more glaring is that in the revised estimates for FY 2024-25, Rs 12,500 cr from the capital outlay is to be returned as unspent. This is a poor reflection on defence mgmt.

The defence allocation for FY (financial year) 2025-26 has been pegged at Rs 6,81,210 crore, which is about \$78.7 billion. This not-so-insignificant amount is 13.45 per cent of the total Central government expenditure (CGE) and has been estimated to be 1.91 per cent of the national GDP. However, there was no mention of the defence allocation in the Budget speech and this opacity is intriguing. Notwithstanding the 'invisibility', this amount needs to be contextualised against various other parameters and the net distillate is that this allocation falls below the optimum fiscal allocation needed to ensure that the combat capability of the Indian armed forces is at an appropriate level. At the global level, in 2024, the military spending of the USA was \$916 billion and China ranked second at \$296 billion. Merits recall that in 2018, the Standing Committee on Defence (SCOD) had recommended 3 per cent of the GDP as the benchmark for the Ministry of Defence to enable the steady irrigation and nurturing of the national ecosystem required to ensure the desired level of preparedness of the armed forces. However, this remains an elusive figure and over the last four years — from 2020-21 to the current FY — the trend has been a declining curve. The defence allocation to GDP percentage has dropped from 2.4 in 2020-21 to 1.91 in 2025-26. This gap has been highlighted over the years, but it is evident that a political decision has been taken by Team Modi that defence allocation will remain depressed even though the regional geopolitical environment and the internal security challenges remain complex and demanding.

The SCOD, in 2018, had also recommended that in the case of the Army — the lead service, which is manpower-intensive — the equipment/inventory mix should ideally be 30 per cent new equipment, 40 per cent current equipment and 30 per cent older-generation equipment. But the reality is grim. In March 2023, the Army, in a candid disclosure, apprised the standing committee "that only 15 per cent of the Army's equipment can be categorised as new equipment, while nearly 45 per cent continued to be older equipment." The Army representative also informed the parliamentary committee that "there is some time to go before we reach the ideal state of 30:40:30."

The composite combat capability of the Indian military has been denuded over the last decade due to inadequate fiscal allocation and indifferent strategic planning. This has been further compounded by the unrelenting, high-decibel focus on 'atmanirbharta' (self-reliance). While the latter objective is indeed desirable when India is seeking a place at the global high table, the reality is not encouraging in terms of combat capability versus indigenisation and self-reliance. M Modi assumed office in 2014 with a commendable resolve to reform India's defence and military sector and identified 'atmanirbharta' as a core mission. A decade later, the overall picture is mixed and opaque.



broad review reveals that while the objective has had a few success stories and some major projects are in the pipeline, the Indian military is dotted with significant inventory deficiencies. These include an army that is short of artillery guns, tanks and personal weapons; a navy waiting for carrier-compatible fighter aircraft and modern underwater platforms; an air force that is woefully short of combat aircraft and a DRDO (Defence Research and Development Organisation) that is unable to deliver as promised. Realising the twin objectives of combat capability and indigenisation, the capital outlay of the defence budget is a critical indicator. An optimum figure is upwards of 35 per cent and here, the picture is bleak. In the current allocation of Rs 6,81,210 crore, the capital outlay is Rs 1,80,000 crore, which is under 27 per cent. An excellent PRS (Parliamentary Research Service) report of July 2024 has highlighted the fact that this capital outlay share "has declined between 2014-15 and 2023-24 to less than 30 per cent of the defence budget." The allocation for this FY is in keeping with this trend line and is unlikely to change in the near future.

What is even more glaring is that in the revised estimates for FY 2024-25, an amount of Rs 12,500 crore from the capital outlay is to be returned as unspent. This is a poor reflection on higher defence management and strategic

planning for a military that is plagued by obsolescence and inventory shortage and must be redressed.

R&D is at the heart of acquiring the much-desired level of technological competence in strategic sectors of national endeavour and here, the Indian space and nuclear domain are islands of proven success. However, the DRDO trajectory in relation to enabling the military to move up the 'atmanirbharta' ladder has been poor. The PRS 2024 report notes that several projects undertaken by the DRDO have been marred by delays and adds: "In an analysis of 178 DRDO projects, CAG observed that 119 projects did not adhere to the original timeline. In 49 projects, the additional time taken was more than the original schedule which was envisaged. Projects have been declared as successful despite them not meeting one or more key objectives and parameters." Year after year, the defence budget goes through this phase of transient scrutiny in the public domain and even while deficiencies are highlighted, the standard refrain is that if there is a need, the purse strings will be opened. This is reactive posturing and when the chips were down, as in Kargil 1999, national sovereignty was retrieved by the loss of life and limb. Redible military preparedness to deter the adversary from adventurism of any kind cannot be realised by prioritising visibility, spectacle and opacity.

Battleground Delhi

BJP looks to turn the tables on AAP

Delhi votes tomorrow after a no-holds-barred election campaign that saw the main contenders giving absolutely no quarter to their rivals. It is expected to be a fight to the finish, unlike the 2015 and 2020 Assembly elections that were reduced to a one-horse race. The Aam Aadmi Party (AAP) knows very well that it won't be a walk in the park this time. The BJP has pulled out all the stops in a bid to remove the thorn in its side — Arvind Kejriwal. However, the former CM, out on bail in a money laundering case linked to the now-scrapped Delhi excise policy, continues to be the face of AAP and a potent threat to the saffron party.

The wily Kejriwal has managed to deflect attention from the 'Sheesh Mahal' row and the corruption charges against him by accusing the BJP government in Haryana of 'poisoning' Yamuna water supplied to Delhi. A notice, promptly issued by the Election Commission on the BJP's complaint, has



forced him to clarify that he was referring to "unprecedented high levels of ammonia in raw water". Nevertheless, BJP leaders have expended a lot of time

and energy on refuting one conspiracy theory after another. This has helped AAP regroup and refocus ahead of voting day.

In this high-stakes battle, the BJP has not shied away from taking the revdi route to woo the electorate. Curiously, voters of the national capital have been resisting the temptation of electing a double-engine government; the Modi magic has been confined to the Lok Sabha elections. In the last roll of the dice, the BJP-led Centre has provided huge relief to the much-taxed middle class, an important vote bank in Delhi. Another factor that gives the BJP hope is the conflict between AAP and the Congress, which are part of the Opposition's INDIA bloc. Both have learnt no lesson from the 2024 fiasco in Haryana, where they played into the BJP's hands by going solo. Their avoidable one-upmanship will have a bearing on the Delhi verdict.



Middle-class voter takes pride of place

Tax relief announced in the Budget goes beyond the need to spur consumption demand

There is a reason why the annual Union Budget grabs attention, even if disproportionate. Embedded in the Finance Minister's speech and the numbers -- the sanctity of which has been questioned in recent years -- are signals on how the government proposes to stabilise the economy and make it grow, and how income and wealth will be redistributed. There are multiple signals sent out through the 2025-26 Budget that reflect the intent of the BJP-led NDA government at the Centre. The strongest signal was reserved for the last paragraph of the FM's speech, when she doled out unexpectedly large sops for the middle-class, salaried taxpayers. The ceiling on tax-free annual income has been raised from Rs 7 lakh to Rs 12.75 lakh (with standard deduction of Rs 75,000). The revised rates in various tax slabs give substantial benefits to those who pay income tax. According to the minister, potential direct tax revenue to the tune of around Rs 1 lakh crore has been foregone to deliver this benefit. These sops have been justified on the ground of spurring consumption demand that has been slack in recent times, contributing to a deceleration in the GDP growth that has troubled the government.

The second signal is a desire to declare that the government is intent on sticking to its efforts at fiscal consolidation by keeping the deficit on a downward "glide path", so as to limit and stabilise the public debt-to-GDP ratio. This is clearly meant to appease foreign investors, who have in recent years rushed into India, and hugely increase the presence of foreign financial investments in the country. Being footloose, this capital can exit at a short notice. Financial investors loathe government deficits, not least because of the fear that they would stoke inflation and erode the real value of financial assets. Fiscal conservatism must be the price to pay to retain the confidence of these investors.

If taxes on the rich as well as corporates recording high profits are not being raised and direct tax sops are being

provided to the middle class, fiscal consolidation can be ensured only by reducing expenditure. This seems to be corroborated by the fact that total expenditure is slated to fall from 14.6 per cent of the GDP in 2024-25 to 14.2 per cent during 2025-26. But a third signal that the Budget sends out is in conflict with the fiscal contraction narrative. That's the government's ostensible intent of raising capital expenditure to support private investment. A lot of that investment is expected to be realised with marginal outlays aimed at incentivising private investments through public private partnerships, but the expenditure figures do point to a 17 per cent hike in capital spending relative to the revised estimates for 2024-25. Optimistic expectations of tax buoyancy and inflated numbers on receipts from non-tax revenue and privatisation partly explain this capacity to raise capital expenditure. But, an important part of the explanation is a willingness to rein in welfare expenditure, including on erstwhile flagship programmes that the NDA government inherited and then claimed credit for. The outlay for the National Rural Employment Guarantee Scheme, having fallen from Rs 90,800 crore in 2022-23 to Rs 86,000 crore in 2024-25, is expected to stay at the same level, even though wage payments are in arrears and demand for jobs is high. Similarly, the food subsidy bill for an enhanced safety net under the National Food Security Act, having fallen from Rs 27.3 lakh crore in 2022-23 to Rs 19.7 lakh crore in 2024-25, is projected at just Rs 20.3 lakh crore in 2025-26. Measures announced in the Budget are sometimes a response to the government's assessment of the prevailing



economic situation. But more often and increasingly so in the 'new India', budgets are instruments in the hands of the ruling party to build vote banks and sway voters. Central budgets are crucial here because of accelerated centralisation of resources in the hands of the Union Government, often at the expense of states (through, for example, the reliance on cesses and surcharges not included in the divisible pool of taxes to be shared with the states as per the constitutional mandate). As a result, the ruling party at the Centre has greater leeway in deploying resources through its own tax and subsidy schemes, and through its choice of Centrally sponsored and Central sector schemes to emphasise upon. Thus, statements from within the ruling coalition and

outside have attributed the FM's direct tax largesse to the need to consolidate a middle-class vote bank, especially with an eye on upcoming state elections, including the one in middle class-dominated Delhi. Special allocation for projects like the Western Kosi Canal extension and renovation, the creation of a Makhana Board to support production of the crop and other forms of assistance for Bihar are clearly driven by the need to appease a key ally, the JD(U), and woo voters in the state that will go to the polls later this year. Meanwhile, governments in Opposition-ruled states — Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal — have complained that their legitimate demand for funds has been ignored. Riding on the analysis in the Economic Survey, which flags the fact that depressed consumption demand and inadequate government capital spending underlie the deceleration in economic growth, the FM claims that tax cuts to boost middle-class demand and increased capital expenditure would help reverse the slowdown. This argument makes the hold on welfare spending a sacrifice needed to revive growth. But an alternative explanation could be that the government expects greater immediate political mileage from consolidating its middle-class vote bank than from providing more support for the weakest sections. The latter, the ruling party possibly believes, have already been won over with the limited support on offer, and by the concerted efforts to attribute to the Centre and the PM the benefits provided under Centrally sponsored schemes that are partly financed by states.

Saluja’s plea against her removal as director rejected

NEW DELHI. In a setback for Rashmi Saluja, executive chairperson of Religare Enterprises (REL), the Delhi High Court (HC) has denied relief to her in a plea against a resolution seeking to replace her with a new director at the upcoming annual general meeting (AGM) on February 7.

Salula had moved the Delhi High Court against her removal as a director of REL, as she had argued that her appointment was for a fixed term of five years till 2028.The decision clears the way for the AGM and the voting on the appointment of a new director to replace Saluja, an important update in the ongoing dispute between the Burman family of Dabur and Saluja. The Burmans open offer to acquire a majority stake in REL is already underway and will close on Friday.

Saluja’s plea has been opposed by four independent directors of REL. Additionally, the proxy firms — Stakeholders Empowerment Services, Institutional Investor Advisory Services, and InGovern Research — have recommended an ‘against’ vote on the resolution pertaining to Saluja’s reappointment, citing concerns over corporate governance, employee stock ownership plans (ESOPs), and higher remuneration. REL described the proxy firm’s reports as ‘orchestrated and motivated’.In addition to Saluja’s plea, minority shareholder Sapna Rao filed a separate case with the Delhi HC to consider the counter-open offer made by Danny Gaekwad. The court on Tuesday stated that SEBI will consider Gaekwad’s offer in accordance with law and that the open offer by Burmans can continue.

Welspun Energy to invest Rs 13,500 crore in Odisha

MUMBAI. Welspun New Energy, green energy arm of Welspun World, has signed a Rs 13,500 crore pact with Odisha to build pumped storage and floating solar projects, which will generate 2,200 mw of green electricity.

In a statement, the company said on Tuesday that Welspun New Energy will invest Rs 13,500 crore to develop 11,200 mw pumped hydro project and a 1,000 mw floating solar power project in the state. These projects are likely to enhance the state’s



energy storage capacity and support the integration of renewable energy into the grid. It announced ongoing make in Odisha conclave in Bhubaneswar.Kapil Maheshwari, the chief executive of Welspun New Energy, said the committed Rs 13,500 crore investment in green mark a key milestone in the state’s mission to accelerate renewable energy adoption and highlights his company’s commitment to innovation and sustainability.

Pumped storage utilises the height difference between the upper and lower reservoirs to store energy with excess wind solar generation and generate electricity during low renewable generation hours.

Growth in services sector slows to more than 2-year low: PMI survey

New Delhi. Growth in India's dominant services sector in January slumped to the slowest in more than two years as demand softened but remained strong and led to a substantial rate of hiring, said a private survey on Wednesday. The HSBC final India Services Purchasing Managers' (PMI) Index, compiled by S&P Global, fell to 56.5 in January from 59.3 in December, lower than a preliminary estimate of 56.8 but ahead of the 50-mark separating contraction from growth. The index has been above the neutral 50-mark that separates contraction from expansion for 42 months straight. “Overall new business continued to increase strongly but the rate of expansion softened to the weakest in 14 months. The rise was attributed to strong demand and decisions to offer better prices than rivals. Growth was reportedly curbed by intense competition,” said the survey.

"The business activity and new business PMI indices eased to their lowest levels since November 2022 and November 2023 respectively," said Pranjul Bhandari, chief India economist at HSBC.

“That said, new export business partly countered the downtrend and continued to rebound from a dip in late-2024, in line with official data which showed India’s services exports shining in December and capturing a larger share of global trade," she said.The survey reported a quicker increase in international sales as respondents noted gains from clients in Asia, Europe, West Asia and the Americas.

International demand in January hit a five-month high. The survey said that new business intakes and capacity pressure prompted service providers to recruit additional staff in the early third quarter of the financial year. “According to them, full- and part-time positions had been filled. The rate of job creation accelerated from December and was among the fastest seen since data collection started in December 2005.” Services firms noted another uptick in expenses, driven by staff costs and food prices. The rate of inflation was little-changed from that seen around the turn of the year, therefore remaining above its long-run average.

Explained: Is China playing it safe in latest trade war with US

US-China trade war: China's countermeasures appear more restrained compared to its approach during the previous trade war. This has raised a key question: Is China playing it safe in the latest trade standoff with the US

NEW DELHI. China has hit back after US President Donald Trump announced new 10% tariffs on Chinese goods. Beijing's response included duties on about 80 American products, an investigation into Google, tighter controls on critical minerals, and the blacklisting of two US companies.However, this time, China's countermeasures appear more restrained compared to its approach during the previous trade war. This has raised a key question: Is China treading cautiously in

the latest trade standoff with the US?The answer lies in Beijing’s current economic challenges and the large trade gap it has with America. Rather than matching Trump’s move entirely, China imposed tariffs on a smaller set of US goods worth around \$14 billion, according to Bloomberg News.The careful response marks a shift from its earlier strategy, when it would retaliate with equal measures against US tariffs.Instead of matching Trump's move completely, China only put tariffs on a small portion of US goods worth \$14 billion, reported Bloomberg News.This careful approach is in stark contrast to how China acted during Trump's first term, when they would match US tariffs dollar for dollar.

WHY CHINA HAS MORE TO LOSE

The change in China’s strategy seems to be due to ongoing economic challenges. The country is dealing with falling prices and trying to fix problems in its property market.Right now, China heavily depends



on selling goods overseas to keep its economy growing.The math makes China's position even more difficult. China sells more than three times as much stuff to the US as it buys from them. This means China has fewer American products it can put tariffs on if it wants to fight back.As Larry Hu from Macquarie Group told Bloomberg, China is being restrained because it "has more to lose" due to this huge trade imbalance with the US.Therefore, instead of getting into a full-blow tariff war, China might focus

more on supporting its own economy through internal measures.Experts suggest China might try to make peace by promising to buy more American oil and gas, keeping its currency stable, or fulfilling previous trade promises.Both sides seem interested in making a deal. Trump has said he wants to talk with Chinese leader Xi Jinping, though he's in no rush. There are other issues on the table too, like Trump wanting China's help to stop the war in Ukraine and demanding changes to TikTok's ownership.For now, China is trying to look strong without making things worse.Josef Gregory Mahoney from Shanghai's East China Normal University told Bloomberg that it's like "two giants sizing each up and testing each other's resolve while also playing to their domestic audiences before shaking hands."But if things escalate, China's heavy reliance on exports to the US means it might have the most to lose in a full-blown trade war.

RBI MPC meeting starts today: Will new Governor Sanjay Malhotra cut rates

New Delhi. The Reserve Bank of India’s (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) meeting begins on Wednesday under the leadership of newly appointed Governor Sanjay Malhotra. This will be the first policy meeting of Sanjay Malhotra as RBI Governor.

Analysts are divided on whether the RBI will cut the repo rate for the first time in nearly two years or maintain the current rate to manage inflation and currency stability.The six-member committee will announce its decision on February 7, 2025.

WILL RBI CUT KEY LENDING RATES?

Experts believe the RBI may reduce the repo rate by 25 basis points (bps) to support economic growth, especially after the Union Budget 2025 focused on boosting demand.he repo rate has been unchanged at 6.5% since February 2023, and the last rate cut was announced during the Covid-19 pandemic in May 2020.

Madan Sabnavis, Chief Economist at Bank of Baroda, believes economic conditions are suitable for a rate cut. The budget has provided a growth stimulus, and inflation is expected to



ease. However, the rupee remains under pressure due to global trade uncertainties,” he said.While some believe a rate cut is likely, others feel the RBI may wait for global economic conditions to stabilise before making any changes.

Edelweiss Mutual Fund predicts a 50 bps rate cut in the first half of 2025, saying that monetary policy will have to play a key role in supporting economic growth.Rumki Majumdar, Economist at Deloitte, believes the RBI will take a cautious approach. “Balancing inflation and credit growth is tricky. While there is pressure to cut rates, the RBI may choose to keep rates unchanged but maintain an easy policy stance,” she said.Umeshkumar Mehta, CIO at SAMCO Mutual Fund, feels that

global factors will influence the RBI’s decision. “Bond yields in the US are rising due to inflation concerns, putting pressure on the Indian rupee. To avoid further depreciation, the RBI may choose to keep rates unchanged,” he explained.

FACTORS THAT COULD IMPACT RATE CUTS

The RBI’s decision will depend on several factors:Inflation trends: Inflation has remained above 5%, but a downward trend could encourage a rate cut.Currency stability: The rupee has been under pressure due to rising US bond yields and global trade tensions.Economic growth: With the government focusing on economic expansion, a rate cut could help boost demand.Global uncertainties: Trade wars and fluctuating commodity prices could impact the RBI’s approach.The stock market and bond markets will react based on the RBI’s decision. If the central bank cuts rates, banking stocks may see gains, and borrowing costs for businesses and individuals could come down. However, if rates remain unchanged, markets may turn volatile as investors adjust their expectations.

Gold consumption in India to cool in 2025 as prices soar, says WGC

New Delhi. India's gold consumption in 2025 is set to moderate from last year's nine-year peak, as a rally in prices to a record high is seen dampening jewellery demand, even as investment demand rises, the World Gold Council (WGC) said on Wednesday. Demand for gold could stand between 700 metric tonnes and 800 metric tonnes, compared to last year's 802.8 tonnes, which was the highest since 2015, Sachin Jain, CEO of WGC's Indian operations, told Reuters. Historically, rising gold prices first affect jewellery customers, and if prices keep rising and remain volatile this year, jewellery demand will be impacted, Jain said. Domestic gold prices hit a record high of Rs 84,399 (\$968.62) per 10 grams on Wednesday. They have risen 10 per



cent so far in 2025 after rising more than 21 per cent in 2024."Households that buy jewellery have a set budget, and when they purchase jewellery, their budget does not increase at the same rate as the rise in gold prices," Jain said. However, the soaring gold prices,

leading to effectively higher returns, are boosting investment demand, which will rise further in 2025 after surging 29 per cent in 2024 to an 11-year high of 239.4 tonnes, he said. Jewellery accounts for nearly 70 per cent of India's total gold demand, while investment demand makes up the rest. "It is anticipated that the trend of robust gold investment demand will continue, with retail investors showing growing interest in gold ETFs, digital gold, and coins and bars," Jain said. (Only the headline and picture of this report may have been reworked by the Business Standard staff; the rest of the content is auto-generated from a syndicated feed.)

Ratan Tata's millennial friend Shantanu Naidu gets top role at Tata Motors

In 2018, Shantanu Naidu began working as Ratan Tata's assistant, a role that brought him public attention, especially after a viral video of his birthday surprise for the industrialist.

New Delhi. Shantanu Naidu, known for his special bond with late industrialist Ratan Tata, was promoted to General Manager, Head of Strategic Initiatives, at Tata Motors after spending more than six years at Tata Sons.Naidu, 32, shared the big career update on LinkedIn. "I'm happy to share that I'm starting a new position as General Manager, Head - Strategic Initiatives at Tata Motors!" he wrote.Turning nostalgic, he added, "I remember when my father used to walk home from the Tata Motors plant in his



white shirt and navy pants, and I would wait for him in the window. It comes full circle now."A mechanical engineering graduate, Shantanu Naidu began his professional journey as an intern at Tata Technologies before joining Tata Elxsi. It was in 2014 that he first caught Ratan Tata’s eye.Naidu, an automobile design engineer, developed a dog collar design with a safety innovation to protect homeless dogs from speeding vehicles.

Tata, a known animal lover, not only decided to invest in the project but also became his mentor.

The industrialist's backing of the initiative marked the beginning of a long-standing professional and personal bond between the two.In 2018, Naidu assumed the role of Tata’s assistant, a position that brought him into the public spotlight. His close relationship with the business tycoon

won hearts, especially after a video of him singing a birthday song for the billionaire philanthropist went viral. Naidu chronicled their unique friendship in his book, I Came Upon a Lighthouse, which offered a rare glimpse into the personality of Ratan Tata beyond his business empire.

Beyond his corporate endeavours, Naidu is also an entrepreneur. In 2021, he founded Goodfellows, a startup dedicated to providing companionship for senior citizens living alone. The venture, valued at Rs 5 crore, received backing from Ratan Tata, who later relinquished ownership of the company.

Following Ratan Tata’s death on October 9, 2024, at the age of 86, Naidu shared an emotional tribute on LinkedIn. "The hole that this friendship has now left with me, I will spend the rest of my life trying to fill. Grief is the price to pay for love. Goodbye, my dear lighthouse," he wrote. According to reports, Naidu's MBA expenses at Cornell University were covered under Tata's will.

New Delhi. Dalal Street saw a strong rally on Tuesday as stock markets surged in the afternoon session, recovering from losses in the previous session.

The benchmark indices, Sensex and Nifty, both closed over 1.5% higher, driven by gains in banking and financial stocks. The S&P BSE Sensex jumped 1,397.07 points to settle at 78,583.81, while the NSE Nifty50 climbed 378.20 points to close at 23,739.25.

According to market experts, the next target range for Nifty stands at 23,900–24,200. The banking sector played a major role in Tuesday’s recovery, and analysts believe that the market’s momentum will depend on how the banking index moves beyond the 50,200 level.Ajit Mishra, SVP-Research at Religare Broking Limited, said, “Given the current market conditions, we continue to focus on selective stock picking, with a preference for large-cap



and large mid-cap stocks.”

Rajesh Bhosale, Technical Analyst at Angel One Ltd., suggested that a buy-on-dips strategy remains ideal, as it has been successful in recent sessions.He added, “The Budget Day high of 23,630 now acts as immediate support, while the bullish gap near 23,400 is a key demand zone.”However, he warned that geopolitical tensions and ongoing trade wars could lead to volatility in the markets. Domestic factors such as the RBI’s Monetary Policy Committee (MPC) meeting and the Delhi state elections will also influence investor sentiment.

Banking stocks have been rising ahead of the RBI policy meeting, where analysts expect a rate cut. This will be the first policy meeting under the new RBI governor, making it a key event for investors.Vinod Nair, Head of Research at Geojit Financial Services, said, “While overall market sentiment remains positive, large-cap stocks are the preferred choice. Meanwhile, banking stocks are rallying in anticipation of a rate cut in this week’s RBI policy.

As Delhi Votes, AAP vs BJP Over Seized 'Promotional Materials', Cops Respond

Issuing a clarification, the police confirmed that some promotional material had been seized, but that it had been taken from booths set up by independent candidates and not those nominated by the BJP.

New Delhi. On Wednesday morning, as voting for the Delhi Assembly election took place, a furious Aam Aadmi Party claimed that promotional material for the opposition Bharatiya Janata Party had been found at some polling booths in the national capital, in violation of the Model Code of Conduct that is in force. The AAP - which has had several tiffs with the Election Commission in this election, including party boss Arvind Kejriwal and Chief Minister Atishi accusing it of bias, a charge firmly refuted last evening - also claimed Delhi Police, which reports to the Union Home Ministry, were "mute spectators".

In a post on X the AAP said, "What is going on? There is election material openly displayed at the BJP booth... and the police are doing nothing. And the election officers are just watching." Issuing a clarification, the police confirmed that some promotional material had been seized, but that it had been taken from booths set up by independent candidates and



not those nominated by the BJP. The AAP also posted a tweet mocking BJP workers leaving a booth; "Run BJP, run. When no one came to the booth, BJP supporters took their chairs and ran... Sweeping is happening all over Delhi." Multiple allegations of election impropriety have been levied by the AAP against the cops today. The party's Greater Kailash MLA, Saurabh Bhardwaj, alleged police were trying to stop people from voting at booths in Chirag Delhi. Speaking to the media,

Mr Bharadwaj claimed the police were putting up barricades and attempting to influence voters in all 18 polling booths there. "You (the cops) have been standing here since morning to influence voting. Why are barricades being put up? Which senior officer of Delhi Police has instructed this? This is being done to disturb poor voters. Malviya Nagar police are openly doing this wherever there is an AAP stronghold of AAP."

South Delhi DCP Ankit Chauhan said the claims would be investigated. "There is an exception for the elderly and those who cannot walk. For them, bringing their car inside is allowed. This rule is being implemented everywhere. We will investigate these concerns," Mr Chauhan told news agency ANI.

The 2015 and 2020 poll were dominated by the AAP, which won 67 and 62 seats, respectively. The BJP and Congress finished a distant second and third. But this time the BJP is hopeful of a strong showing to upset Mr Kejriwal's chances of a third successive term in the national capital.

Arvind Kejriwal Goes To Vote With Family, Parents In Wheelchairs

New Delhi. As Delhi voted to elect its new government, Arvind Kejriwal, former Chief Minister and the ruling Aam Aadmi Party's (AAP) national convener cast his vote along with his family in the New Delhi Assembly segment, where he is also a candidate. Mr Kejriwal arrived at the polling booth in Lady Irwin Senior Secondary School along with his parents, wife and son. His elderly parents Gobind Ram Kejriwal and Gita Devi were on wheelchairs. While Mr Kejriwal pushed his mother's wheelchair, his son Pulkit pushed his



father's. His wife Sunita walked alongside them. Earlier today, Mr Kejriwal urged voters of the national capital to vote for development and honesty. He also hoped that "hooliganism" would lose and Delhi would win.

Dear Delhi residents, today is election day. Your vote is not just a button but a foundation for your children's bright future. Good schools, good hospitals and an opportunity to give every family a dignified life. Today, we have to defeat the politics of lies, hate and fear and make development and honesty win. Vote and inspire your family, friends and neighbours. Hooliganism will lose, Delhi will win," he said.

The New Delhi constituency, which has elected Mr Kejriwal in the 2013, 2015 and 2020 polls, is witnessing a three-cornered contest this time. Mr Kejriwal is up against the BJP's Parvesh Verma and the Congress's Sandeep Dikshit. Both are sons of former Chief Ministers.

A total of 699 candidates are in the contest for 70 Assembly seats in the national capital. Delhi has 1.5 crore registered voters, including 83.76 lakh men, 72.36 lakh women and 1,267 from the third gender. In the 2020 polls, AAP won 62 seats and the BJP eight.

Delhi HC seeks SC clarification on court jurisdiction for Engineer Rashid's bail plea

NEW DELHI. The Delhi High Court has approached the Supreme Court seeking clarification regarding the appropriate trial court to hear the bail plea of Baramulla MP Engineer Rashid, currently imprisoned in a terror funding case under the Unlawful Activities (Prevention) Act. The issue arose after the special NIA court, which had reserved its order on Rashid's bail plea, later transferred the matter, stating that only a designated MP/MLA court has jurisdiction to hear cases involving elected lawmakers.

Justice Vikas Mahajan, while hearing Rashid's petition for an expedited bail decision, directed the Delhi High Court's Registrar General to obtain clarification from the Supreme Court on the matter.

The case is now listed for further hearing on February 6. Rashid has also sought interim bail to attend the ongoing Budget session of Parliament. Senior Advocate N Hariharan, representing Rashid, argued that his client had been granted interim bail in the past, including instances when he was campaigning during the Jammu and Kashmir elections. "I am ready to address all objections, but for now, I am only requesting interim bail. The merits of the case can be discussed later," Hariharan submitted.

Opposing the request, Senior Advocate Sidharth Luthra, appearing for the National Investigation Agency (NIA), contended that Rashid's bail plea must be heard by a division bench as per the NIA Act. However, the high court noted that Rashid had been granted interim bail multiple times in the past without any allegations of misuse.

Pictures of Indians getting handcuffed, humiliated while being deported from US saddening: Congress

NEW DELHI. The Congress on Wednesday expressed sadness over "pictures of Indians getting handcuffed and humiliated" while being deported from the US and recalled that America had to express regret over the treatment meted out to India diplomat Devyani Khobragade in 2013 after the then UPA government retaliated sharply.

A military transport aircraft of the US is bringing a group of Indian migrants, in the first such deportation to India as part of the big crackdown on illegal immigrants by President Donald Trump in his second term at the White House. Without directly commenting on the deportation flight carrying the Indians, a spokesperson at the US embassy in New Delhi said on Tuesday that Washington is tightening immigration laws and removing illegal migrants.

Congress' media and publicity department head Pawan Khhera said, "Looking at the pictures of Indians getting handcuffed and humiliated while being deported from the US saddens me as an Indian." "I remember in December of 2013, an Indian diplomat Devyani Khobragade was handcuffed and strip searched in America. Foreign Secretary Sujatha Singh registered a strong protest with US Ambassador Nancy Powell," Khhera said in a post on X.

"The UPA government retaliated sharply. Leaders like Ms Meira Kumar, Sushil Kumar Shinde & Rahul Gandhi refused to meet the US Congressional delegation (George Holding, Pete Olson, David Schweikert, Rob Woodall and Madeleine Bordallo) that was visiting India at that time," he recalled. Khhera said then PM Manmohan Singh termed the US action 'deplorable'.

India withdrew several perks given to the US embassy, including imports of food and alcohol at concessional rates by embassy staff, he said.

Centre says will give Rs 25L to trust for construction of Singh memorial

NEW DELHI. The Centre is ready to allocate land and funds to the trust to be set up to construct the memorial for former Prime Minister Manmohan Singh. Sources said the government would give Rs 25 lakh to the trust to be formed by Singh's family. Sources said the government has thrice reminded the family, but the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHA), the nodal agency for land allotment, is still awaiting a response from them. Singh passed away last December. Following the demand by Congress president Mallikarjun Kharge, the government offered two adjoining plots at the Rashtriya Smriti complex for his memorial. The ministry also carried out groundwork to facilitate its construction. This newspaper also reported that the architect of the Central Public Work Department (CPWD) inspected the two pieces of land — measuring about 10,000 square feet — and later discussed the memorial's design and other modalities.

The selected sites are close to the memorials of former presidents and prime ministers such as Giani Zail Singh, Shankar Dayal Sharma, Chandra Shekhar, I.K. Gujral, and P.V. Narasimha Rao.

According to government officials, the CPWD will carry out the construction, and the trust will bear the expenses. The proposed memorial's cenotaph would be identical to those already existing on the campus.

Each memorial is a square piece of land surrounded by about two-foot-high sandstone-latticed screens with a 5X5 black granite platform in the centre. This is the standard design for memorials at the Rashtriya Smriti complex.

The only exception is Atal Bihari Vajpayee's Samadhi. It comprises nine square black polished granite solid stone blocks, capped with a 'diya' in the Centre. The blocks are placed in a circular lotus-shaped pattern and enclosed by nine bas-relief walls, which have inscriptions of the prose or poetry of Vajpayee.

Memorial plots at Rashtriya Smriti Sthal
Dr Manmohan Singh passed away last December. Following the demand by Congress president Mallikarjun Kharge, the government offered two adjoining plots at the Rashtriya Smriti complex for his memorial.

BJP accuses AAP of trying to block votes from key communities ahead of Delhi polls

NEW DELHI. A day before the Delhi assembly elections, BJP president Virendra Sachdeva accused the Aam Aadmi Party (AAP) of attempting to prevent votes from key communities, including the Vaishya, Brahmin, and Purvanchal groups.

Sachdeva alleged that AAP leaders had submitted lists to election officials in nearly 50 constituencies, claiming that thousands of Purvanchali, Vaishya, and Brahmin voters were either deceased or no longer residing at their registered addresses, and thus should be disqualified from voting. To support his claim, Sachdeva presented around 15 individuals whose voting eligibility had been questioned by AAP, yet were confirmed to be

present and qualified to vote. He accused AAP of attempting to block these voters, particularly Purvanchalis, from voting early in the



day, with the intention of disrupting the election process and influencing the outcome.

Sachdeva urged the Election Commission (EC) to dismiss any

objections raised by political parties and allow all voters listed in the official Booth Level Officer (BLO) records to cast their votes without hindrance.

"The AAP wants to influence the voting process by creating long queues at polling booths, thus reducing voter turnout where BJP is strong," Sachdeva said. "If you deny the legitimate voters of Delhi their right to vote, the people will punish you at the polls. If you are losing the election, accept it. Do not steal the votes of Delhi's citizens." The BJP has formally complained to the EC, calling for immediate action to prevent any interference with the voting process. The intense campaigning for the assembly polls ended on Monday, with the top leadership of all parties canvassing for their candidates.

Before Oxford and Harvard, there was Nalanda

NEW DELHI. Established in 427 CE, Nalanda University in present-day Bihar, was home to one of the world's first great universities, thriving centuries before Oxford and Harvard. However, its foundation dates back even further. To honour Sariputra, one of Buddha's chief disciples, Mauryan emperor Ashoka built a stupa at the site in the third century BCE, which became the nucleus of the Nalanda Mahavihara. Beside it, he constructed a vihara (monastery) for Buddhist monks, which gradually evolved into the Nalanda Mahavihara — one of the greatest centres of learning in the ancient world.

Abhay K, author and diplomat

In his new book, *Nalanda: How It Changed the World* (Penguin), author and diplomat Abhay K. threads together the many stories and events associated with the university and its

vast history. The book spans eight chapters, covering episodes from the time of Bimbisara, who established the Haryanka dynasty in Magadha, to Nalanda's relevance and impact in the current global scenario.

Growing up in Nalanda, Abhay regularly visited the ruins of the



Nalanda Mahavihara. "I used to read the small locally printed booklets sold on the footpath there, which carried information in bits and pieces about the founding of the great

monastery," he recalls. These early visits to the ruins and the stories told by local guides sparked his lifelong curiosity and gave him a unique perspective, allowing him to bring a personal touch to his portrayal of Nalanda's history.

The rise and fall

Despite the challenges of navigating through extensive historical data, much of which is shrouded in mystery, Abhay makes the narrative engaging by channeling his curiosity into answering the many questions that arose in his mind. "I was fascinated by the origins of the vihara at Nalanda — how and why it became such a celebrated seat of learning and its legacy beyond the 14th century," he says. His aim was to gather information from reliable sources, connecting the dots across different time periods to create a comprehensive account.

Delhi sees cloudy skies, light rain as IMD forecasts mix of rain, fog ahead

As per the IMD bulletin, fog will dominate the morning scene in the capital from February 5 onward.

NEW DELHI. The national capital woke up to a cloudy morning skies with light rainfall in parts of the city on Tuesday with the India Meteorological Department (IMD) forecasting light showers throughout the day. On Wednesday the sky is likely to remain clear, the weather office said. Smog and shallow fog are expected in most places in early morning, with moderate fog in isolated areas, it added.

As of 5 pm on Tuesday, the Safdarjung weather station recorded 0.5 mm



rainfall. The minimum temperature settled at 12.8 degrees Celsius, 4.4 degrees above average, while the maximum temperature was 26 degrees Celsius, 3.7 notches above normal, as per IMD. Humidity levels fluctuated between 91 and 76 per cent during the day, while the air quality remained in the "poor" category, with average Air

Quality Index (AQI) recorded 264.

As per sources, Delhi weather is likely to take a U-turn from sunny mornings, returning to colder morning conditions. This week, the national capital is slated to experience a mix of rain and foggy conditions.

As per the IMD bulletin, fog will dominate the morning-scene in the

capital from February 5 onward. Temperatures are likely to hover between 9°C to 25°C in the coming days.

Meanwhile, the city witnessed its hottest January since 2019, attributed to lack of rain-bringing western disturbances.

Hottest January since 2019

This year, the national capital experienced its warmest January since 2019, with an average maximum temperature of 21.1°C, slightly above the long-term average of 20.1°C.

IMD data has indicates higher-than-usual night temperatures. Meteorologists have attributed this warmth to lack of strong western disturbances, which typically bring rain and cooler conditions. "This month, while western disturbances did pass through North India, most of them were feeble and did not bring significant snow or rainfall," expert Mahesh Palawat said.

NEWS BOX

CIA offers buyouts to its entire workforce: Report

WASHINGTON.The US Central Intelligence Agency offered buyouts to its entire workforce on Tuesday, the Wall Street Journal reported.The move would make it the first intelligence agency to join a voluntary redundancy program initiated by President Donald Trump for federal employees.

The agency is also freezing the hiring of job seekers already given a conditional offer, the paper reported, citing an aide to CIA Director John Ratcliffe.

The anonymous aide said some of those frozen offers are likely to be rescinded if the applicants do not have the right background for the agency's new goals, which include targeting drug cartels, Trump's trade war and undermining China, according to the Journal.he move is part of a massive overhaul of the US government by Trump, who has vowed to radically downsize the federal workforce in the name of efficiency and frugality that has sent shock waves through Washington.

The report on the buyout offers at the CIA -- whose work gathering foreign intelligence is vital to US national security -- came just hours after Trump announced an extraordinary scheme for the United States to "take over the Gaza Strip."

India Featured In UN's Honour Roll For Timely Payment Of Regular Budget



New York. The Permanent Mission of India in New York announced on Tuesday that India has once again been included in the 'Honour Roll' of the United Nations (UN) for paying its regular budget assessments in full within the 30-day period specified in the Financial Regulations of the UN.

In a statement, the Mission said, "India yet again featured in the 'Honor Roll' of UN as one of the countries that have paid their regular budget assessments in full within the 30 day period specified in Financial Regulation 3.5 of the UN. The Honour Roll includes select Member States that have successfully fulfilled their financial commitment to the UN within 30 days of receiving a payment note."

The UN General Assembly approves UN's Regular Budget in December each year. Each Member State is then assessed based on the Scale of Assessment approved by the General Assembly, and corresponding payment notes are issued by the UN in early January.The statement emphasized that India has consistently figured on the UN's Honour Roll."India's promptness in making contributions to the UN demonstrates its unwavering support to the principles and purposes enshrined in the UN Charter and commitment to upholding the financial stability and operational effectiveness of the UN", the statement highlighted adding, this further reaffirms India's role as a responsible member of the UN.

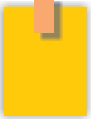
Iran Is Secretly Developing Nuclear Missiles Capable Of Hitting Europe, Claims Report



World Iran is secretly developing nuclear missiles with the ability to reach Europe based on designs handed to the Islamic regime by North Korea, a new report released by the National Council of Resistance of Iran (NCRI) claimed. According to the report, the weapons are being produced at two sites disguised as satellite launch facilities. The NCRI, an exiled opposition group, said that Tehran is expediting its alleged nuclear weapons program at these facilities. It also stated that the missiles are capable of travelling more than 3,000 km (1,800) miles, potentially targeting Europe. Citing the report, the New York Post reported that one of the facilities the NCRI flagged as a nuclear weapons site was the Shahrud missiles facility, which is being run by Iran's Organization for Advanced Defense Research and Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). The group believes that the nuclear warhead being developed at the site would be fitted on a Ghaem-100 missile and would be capable of reaching as far as Greece. It also estimates that Iran has already tested the rocket launchers at the Shahrud facility at least three times. Those rocket launches were allegedly concealed as part of satellite launches, the NCRI claims. It believes that IRGC is planning to test launch more advanced Ghaem rockets in the coming months.The second testing facility is believed to be located more than 43 miles southeast of Semnan, where Tehran is developing Simorgh missiles based on North Korean designs. In its report, the NCRI said that portions of this site are hidden underground. It also accused Tehran of expanding this site since 2005.

Mr Armstrong revealed he was on a hunting trip with friends that turned into a nightmare. "I didn't think much of it as I have gotten burns.

Gaza Strip has long been a powder keg. Here's a look at the history of the embattled region



Trump's suggestion that displaced Palestinians in Gaza be permanently resettled outside the war-torn territory and the US take "ownership" may spark new tension over the enclave.

JERUSALEM. Gaza has long been a powder keg, and it exploded after Hamas fighters stormed southern Israel on Oct. 7, 2023, and began killing and abducting people, sparking a crushing Israeli military operation there that's only recently reached an uneasy ceasefire.US President Donald Trump's suggestion Tuesday that displaced Palestinians in Gaza be permanently resettled outside the war-torn territory and the US take "ownership" may spark new tension over the enclave on the Mediterranean Sea.Here's a look at the troubled modern history of the Gaza Strip:

1948 - 1967: Egyptian rule o GazaBefore the war surrounding Israel's establishment in 1948, present-day Gaza was part of the large swath of the Middle East under British colonial rule. After Israel defeated the coalition of Arab states, the Egyptian army was left in control of a small strip of land wedged between Israel, Egypt and the Mediterranean.During the war, some 700,000 Palestinians either fled or were forced from their homes in what is now

Israel—a mass uprooting that they call the Nakba, or "catastrophe." Tens of thousands of Palestinians flocked to the strip.Under Egyptian military control, Palestinian refugees in Gaza were stuck, homeless and stateless. Egypt didn't consider them to be citizens and Israel wouldn't let them return to their homes. Many were supported by UNWRA, the United Nations agency for Palestinian refugees, which has a heavy presence in Gaza to this day. Meanwhile, some young Palestinians became "fedayeen"—insurgency fighters who conducted raids into Israel.

1967 - 1993: Israel seizes control

Israel seized control of Gaza from Egypt during the 1967 Mideast war, when it also captured the West Bank and east Jerusalem—areas that remain under Israeli control. The internationally recognized Palestinian Authority, which administers semi-autonomous areas of the occupied West Bank, seeks all three areas for a



hoped-for future state.Israel built more than 20 Jewish settlements in Gaza during this period. It also signed a peace treaty with Egypt at Camp David—a pact negotiated by US President Jimmy Carter.

Egyptian President Abdel Fattah el-Sissi has referenced this 40-year old treaty when he declined to permit Palestinian refugees from Gaza into Egypt, saying the potential entrance of militants into Egypt would threaten longstanding peace between Israel and Egypt.The first Palestinian uprising against Israeli occupation erupted in Gaza in December 1987, kicking off more than

five years of sustained protests and bloody violence. It was also during this time that the Islamic militant group Hamas was established in Gaza.1993 - 2005: The Palestinian Authority takes chargeFor a time, promising peace talks between Israeli and Palestinian leaders made the future of Gaza look somewhat hopeful.Following the Oslo accords—a set of agreements between Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin and Palestinian Liberation Organization leader Yasser Arafat that laid the groundwork for a two-state solution—control of Gaza was handed to the fledgling Palestinian Authority.But the optimism was short lived. A series of Palestinian suicide attacks by Hamas militants, the 1995 assassination of Rabin by a Jewish ultranationalist opposed to his peacemaking and the election of Benjamin Netanyahu as prime minister the following year all hindered US-led peace efforts. Another peace push collapsed in late 2000 with the eruption of the second Palestinian uprising.

Trump to sign executive order barring transgender female athletes in US from competing

WASHINGTON. US President Donald Trump will sign an executive order on Wednesday designed to prevent people who were biologically assigned male at birth from participating in women's or girls' sporting events.The order, which Trump is expected to sign at an afternoon ceremony, marks another aggressive shift by the president's second administration in the way the federal government deals with transgender people and their rights.

The president put out a sweeping order on his first day in office last month that called for the federal government to define sex as only male or female and for that to be reflected on official documents such as passports and in policies such as federal prison assignments.rump found during the campaign that his pledge to "keep men out of women's sports" resonated beyond the usual party lines. More than half the voters surveyed by AP VoteCast said support for transgender rights in government and society has gone too far. He leaned into the rhetoric before the election, pledging to get rid of the "transgender insanity," though

his campaign offered little in the way of details.Wednesday's order—which coincides with National Girls and



Women in Sports Day—will involve how his administration will interpret Title IX, the law best known for its role in pursuing gender equity in athletics and preventing sexual harassment on campuses."This executive order restores fairness, upholds Title IX's original intent, and defends the rights of female athletes who have worked their whole lives to compete at the highest levels," said US Rep. Nancy Mace, a Republican from South Carolina.Every administration has the authority to issue its own

interpretations of the landmark legislation. The last two presidential administrations—including Trump's first—offer a glimpse at the push-pull involved.Betsy DeVos, the education secretary during Trump's first term, issued a Title IX policy in 2020 that narrowed the definition of sexual harassment and required colleges to investigate claims only if they're reported to certain officials.The Biden administration rolled back that policy last April with one of its own that stipulated the rights of LGBTQ+ students would be protected by federal law and provided new safeguards for victims of campus sexual assault. The policy stopped short of explicitly addressing transgender athletes. Still, more than a half-dozen Republican-led states immediately challenged the new rule in court."All Trump has to say is, 'We are going to read the regulation traditionally,'" said Doriane Lambelet Coleman, a professor at Duke Law School.How this order could affect the transgender athlete population—a number that is incredibly difficult to pin down—is uncertain.

About 10 killed at adult education centre in what officials say is Sweden's worst mass shooting

World Swedish police said that about 10 people, including the gunman, were killed during a shooting Tuesday at an adult education center. But a final death toll and a conclusive number of wounded hadn't yet been determined.The damage at the crime scene was so extensive that investigators were unable to be more definitive, said Roberto Eid Forest, head of the local police. The shooting happened on the outskirts of the city of Orebro, which is located about 200 kilometers (125 miles) west of Stockholm.Police said that the death toll could rise. Eid Forest told reporters that the suspected gunman was among those killed. Police believe the perpetrator acted alone, and he wasn't previously known to police, officials said.Authorities said that there were no suspected connections to terrorism at this point, but police didn't provide a motive.The school, called Camus

Risbergsgka, serves students who are over age 20, according to its website. Primary and upper secondary school courses are offered, as well as Swedish classes for immigrants, vocational training and programs for people with intellectual disabilities.Gun violence at schools is very rare in Sweden. But there have been several incidents in recent years in which people were wounded or killed with other weapons such as knives or axes.Police raided the suspect's home after Tuesday's shooting, but it wasn't immediately clear what they found. Eid Forest said there were no warning signs before the attack. Authorities were working to identify the deceased.Prime Minister Ulf Kristersson will hold a news conference at 7:30 p.m. local time (1830 GMT) alongside Justice Minister Gunnar Strömmer,Earlier, Kristersson said that it was "a very painful day for all of Sweden," Swedish media

reported."My thoughts are also with all those whose normal school day was exchanged for terror," Kristersson said. "Being confined to a classroom with fear for your own life is a nightmare that no one should have to experience."Swedish King Carl XVI Gustaf praised police and the rescue and medical personnel who responded to the shooting, and issued words of comfort to the families of the victims.Prime Minister Ulf Kristersson will hold a news conference at 7:30 p.m. local time (1830 GMT) alongside Justice Minister Gunnar Strömmer,Earlier, Kristersson said that it was "a very painful day for all of Sweden." Swedish media reported."My thoughts are also with all those whose normal school day was exchanged for terror," Kristersson said. "Being confined to a classroom with fear for your own life is a nightmare that no one should have to experience.



importance of acquiring skills and education to access opportunities worldwide.He encouraged people to research legal ways, acquire education and language skills before travelling abroad.After Donald Trump assumed office as the US President last month, the country's law enforcement agencies have launched a crackdown against illegal immigrants.

Many people from Punjab, who entered the US through "donkey routes" or other illegal means by spending lakhs of rupees, are now facing deportation.

South Africa President Needed To Call Elon Musk. Tesla Head's Father Helps Him



So Bejani Chauke, an adviser to Cyril Ramaphosa, the South African president, called Musk's father, Errol, a 78-year-old engineer who lives in a luxury double-storey coastal villa.

Langebaan, South Africa.South Africa's president needed to call Elon Musk on Monday evening.The billionaire had publicly accused his post-apartheid government of anti-white racism, and now Musk's ally, US President Donald Trump, said he would cut more than \$400 million in funding to the country.So Bejani Chauke, an adviser to Cyril Ramaphosa, the South African president, called Musk's father, Errol, a 78-year-old engineer who lives in a luxury double-storey coastal villa a two-hour drive from Cape Town, Musk senior said."I was asked if I can arrange a quick talk between Ramaphosa and Elon last night...so I did and then they spoke a few minutes later," Errol Musk told Reuters at his home in Langebaan, a mostly white enclave looking onto a lagoon fed by the Atlantic Ocean where he keeps a Bentley and a Rolls-Royce.He briefly showed an

exchange of WhatsApp messages between himself and Chauke that backed up his account. Chauke did not respond to questions by Reuters about his role in contacting Musk's father. Ramaphosa's office confirmed the phone conversation with Elon Musk, who was born in South Africa, in a post on the tycoon's X social media platform.Contactd by Reuters, Ramaphosa's spokesperson declined to comment on how the conversation with Elon Musk came about or on its content, only saying: "Errol Musk is a private citizen, his views are his personal views."Elon Musk did not reply to multiple requests for comment from Reuters.The trigger for the sudden flurry of backdoor diplomacy was a post on Sunday by Trump who said - without citing evidence - that "South Africa is confiscating land" and "certain classes of people" were being



treated "very badly".He added that he would cut off funding to the country in response, prompting a nearly 2% slide in South Africa's rand in early trading on Monday, and a fall in stocks and government bonds. The cost of insuring South African debt against default rose to its highest since early August.rump was referring to a bill signed into law by

Ramaphosa last month with the aim of addressing racial disparities in land ownership that have persisted in South Africa since apartheid ended 30 years ago -- a target of public criticism by Elon Musk and many white farmers.The law allows the state to expropriate land "in the public interest", in some cases without compensating the owner. South Africa had previously set a target for the government to transfer 30% of farmland to Black hands that has been repeatedly pushed back. As of 2018, only 8% had been transferred, according to a government survey of title deeds.White landowners possess three quarters of South Africa's freehold farmland, compared with 4% for Black landowners, according to the most recent state audit. Black people make up about 80% of South Africa's total population.

NEWS BOX

Pat Cummins likely to miss
Champions Trophy, Steve Smith
or Head to lead Australia

New Delhi. Australia coach Andrew McDonald hinted that captain Pat Cummins is likely to miss the ICC Men's Champions Trophy due to his ankle issue. The Australian coach also said that Steve Smith and Travis Head are in contention to lead Australia in the ICC tournament.Cummins skipped the Test tour of Sri Lanka for the birth of his second child while also managing an ankle issue that worsened after a demanding Border-Gavaskar Trophy. Australia's ODI squad members, who were not involved in the Test series, are set to fly out for Sri Lanka on Thursday. However, McDonald indicated on Wednesday morning that Cummins is unlikely to join them."Pat Cummins hasn't been able to resume any type of bowling so he's heavily unlikely, so that would mean that we do need a captain," McDonald told SEN. "Steve Smith and Travis Head are the two that we've been having conversations with while we've been building out that Champions Trophy team along with Pat back home. They'll be the two that we look at for that leadership post.McDonald praised Smith's leadership credentials, highlighting his experience in Test and ODI cricket."They're the two obvious ones. Steve has done a great job here in the [first] Test match. He's done some good work in one-day international cricket across the journey as well. So it's between those two."But, as I said, Patty is



hugely unlikely, which is a bit of shame, and we've also got Josh Hazlewood, who is battling [to be fit] at the moment. So that medical information will land over the next couple of days and we'll be able to shore that up and let everyone know the direction."Meanwhile, Josh Hazlewood's availability also remains uncertain. Hazlewood is nursing a hip issue after recovering from side and calf injuries that sidelined him for much of the India series and the Sri Lanka tour. Mitchell Marsh has been ruled out of the Champions Trophy with a back injury and is unlikely to feature in the domestic season, though he may still play in the IPL for Lucknow Super Giants.Australia are yet to name a replacement for Marsh. Coach Andrew McDonald confirmed.s

Parunika Sisodia absorbs
Laxman pep-talk, Mithali
Raj advice to live World
Cup dream

New Delhi. It didn't quite seem all that pleasant for India as they vied for a berth in the summit clash of the U19 Women's T20 World Cup. Davina Perrin was breathing fire in the semi-final with her breathtaking strokes as England raced to 37 without loss in the first four overs. But a certain left-arm spinner had other ideas. 19-year-old Parunika Sisodia was in no mood to throw in the towel.In the fifth over, she castled Jemima Spence with a delivery that went on with the arm. Two balls later, Parunika cleaned up Trudy Johnson down the leg side. India didn't look back from there on as England scored only 76 runs off their last 93 balls, finishing at 113 for eight. All it took for India was 15 overs to chase down the



target, and it was Parunika who became the Player of the Match. The match against England was the only instance when India found themselves in a spot of bother throughout the tournament, but Parunika's match-winning spell of 4-0-21-3 powered them past the finish line. Parunika did not find a place in the Team of the Tournament where her spin bowling partners, Aayushi Shukla and Vaishnavi Sharma, and India's openers, Gongadi Trisha and G Kamalini, featured.But Parunika had an economy rate of 2.71, the best amongst all the Indian bowlers. In fact, none of the Indians had an economy rate of less than three, with Aayushi's 3.01 being the second-best. Parunika picked up 10 wickets from six matches, backing up her stupendous performance in India's title-winning campaign in the U19 Asia Cup, where she shone with nine scalps at an economy rate of 4.22.

Rohit Sharma's ODI batting has been game-changing, helped team a lot: Shubman Gill

Shubman Gill feels that Rohit Sharma's ODI batting has been a game changer for the Indian team in recent times. Rohit started using the attacking template during the ODI World Cup 2023.

New Delhi. Shubman Gill has claimed that Rohit Sharma's ODI batting has been a game-changer for the Indian team as the captain continues to lead from the front with his aggressive intent. Rohit started using this template during the ODI World Cup 2023, scoring 597 runs with an impressive strike rate of 125.94. The Indian skipper continued to use this mantra during India's T20 World Cup triumph. Even during India's tour of Sri Lanka, Rohit scored 157 runs in 3 matches with a strike-rate of 141.44. Speaking at the press



conference ahead of the Nagpur ODI, Gill said that Rohit manages to take the momentum right from the start and it makes the job of the non-striker and the other batters easier."The way Rohit bhai has been

batting in the ODIs in the past one year and a half, it's been really game-changing for us.""Taking the momentum right through from the start and taking the game away from ball one, and it makes the job of the

England hopeful wicketkeeper Jamie Smith will recover in time for Champions Trophy

New Delhi England remain optimistic that Jamie Smith will recover in time to participate in the ICC Men's Champions Trophy later this month, despite confirming his absence from the first two ODIs against India.The Surrey wicketkeeper-batsman experienced calf discomfort during the third T20 international in Rajkot, which marked England's only victory of the series. Since then, Smith has been undergoing treatment in an effort to regain full fitness.England plan to assess Smith's fitness in the final match of the tour in Ahmedabad next Wednesday, which coincides with the deadline for submitting finalised Champions Trophy squads to the International Cricket Council (ICC).Smith's injury setback means he will miss the initial two ODIs against India, with England hoping he can return in time for their last 50-over fixture before the Champions Trophy opener against Australia on February 22.The three-match ODI series



begins in Nagpur on Thursday, with the second match scheduled for Sunday. Joe Root has rejoined the squad for the ODI leg, providing some much-needed experience to a batting line-up that struggled during the T20 series. Smith's absence further limits England's options at the top of the order. Phil Salt and Ben Duckett are expected to open, with Root slotting in at number three for his first 50-over international appearance

since the 2023 World Cup. Captain Jos Buttler, Harry Brook, Liam Livingstone, and Jacob Bethell make up England's middle-order options.Rehan Ahmed, who was initially only selected for the T20 series, has been retained for the ODIs. Although he did not feature in the T20s, England now have the option of pairing him with fellow leg-spinner Adil Rashid in the 50-over format.

India have made a notable addition to their squad, bringing in spinner Varun Chakravarth after his standout performance in the T20 series, where he finished as the leading wicket-taker with 14 scalps at an average of 9.85. The 33-year-old is uncapped in ODIs and has only played 23 List A games in his career. India also welcome back key senior players, including captain Rohit Sharma, Virat Kohli, and wicketkeeper Rishabh Pant. However, there is no place for Abhishek Sharma, who hit a century in the fifth T20 in Mumbai.

Rashid Khan breaks Bravo's record to become highest wicket-taker in T20 cricket

Highest T20 wicket-taker: Afghanistan legspinner Rashid Khan became the highest wicket-taker in the history of T20 cricket. Rashid took his wicket tally to 633 in T20s — better than West Indies legend Dwayne Bravo.

New Delhi. Star Afghanistan spinner Rashid Khan scripted history by surpassing West Indies legend Dwayne Bravo to become the leading wicket-taker in T20 cricket. Rashid achieved this remarkable feat during MI Cape Town's Qualifier One match against Paarl Royals in the SA20 league."It's a great achievement," Rashid told the broadcaster. "I never thought about it, if you asked 10 years before this if I would get there. It's a proud feeling to be from Afghanistan and to be at that level where you top the table. DJ (Bravo) is one of the best T20 bowlers. It's a great honour and I'm looking forward to continuing."Rashid now boasts an



Dwayne Bravo: 631
Sunil Narine: 574
Imran Tahir: 531
Shakib Al Hasan: 492
Rashid remains one of the most sought-after players in T20 leagues worldwide, plying his trade in prestigious tournaments such as the IPL, BBL, CPL, SA20, The Hundred, ILT20, and MLC. His T20 journey began in 2015 when he made his debut for Afghanistan at just 17 years old against Zimbabwe. Since then, he has established himself as one of the format's most formidable bowlers, deceiving batsmen across the globe.MI Cape Town put up a strong total of 199/4 after Paarl Royals elected to field first. The opening duo of Ryan Rickelton and Rassie van der Dussen laid a solid foundation with an 87-run stand in just 9.2 overs. Despite a minor setback with three wickets falling for just six runs, George Linde's quickfire 26 off 14 balls swung the momentum back in MI Cape Town's favour. Deward Brevis and Delano Potgieter capitalised on wayward bowling to add 74 runs in the final five overs.

Highest T20 wicket-takers:
Rashid Khan: 633

Kohli, I've never seen you bat this slowly: Cummins sledges India batter in new ad

Australia captain Pat Cummins was seen sledging star India batter Virat Kohli in a new advertisement for the ICC Champions Trophy 2025.

New Delhi. Australia captain Pat Cummins was recently seen practicing to sledge star India batter Virat Kohli in an advertisement for the ICC Champions Trophy 2025. Virat Kohli will be one of the batters to watch out for in the tournament which is scheduled to begin from February 19. Hence, ahead of the mega event, Cummins was seen rehearsing how to disturb Kohli's rhythm when he comes out to bat against him in the event. The hilarious clip from the advertisement shows Cummins shaving as he looks into the mirror



and comments on the strike rate of the India star. The viral video has gained massive traction on social media with people loving Cummins' hilarious side. "He Kohli, I've never seen you bat this slowly. Slowly!," said Cummins in the viral video.Cummins' participation in doubt

Meanwhile, Cummins is likely to be ruled out of the Champions Trophy as head coach Andrew McDonald recently hinted that he's unlikely to join the team. Cummins skipped Australia's ongoing Test tour of Sri Lanka for the birth of his second child while also managing an ankle issue that worsened after

non-striker and the batsmen coming in a bit easier and I think it has helped our team a lot," said Gill.India haven't had the best of times in the longer formats of the game as they lost the Border-Gavaskar Trophy to Australia. The form of many of the senior players, including Gill, was questioned after the completion of the tour. The Indian vice-captain said that one series doesn't define the form of the whole team. "One series does not define the form of the whole team. There are a lot of players who, in the past, have performed consistently in a lot of series and tournaments," Gill told reporters here ahead of the first ODI against England."Definitely, we did not play as per our expectations in the Australian series, but still we played some good cricket. We were unfortunate not to have (Jasprit) Bumrah on the last day and we would have won the match and the series would have been a draw and this talk wouldn't have happened."One match and one day doesn't define us, we won there twice before and earlier won a World Cup, and then reached the final of a World Cup, so we should keep all those things in mind."

Brendon McCullum backs England to win ODIs vs India with 'hostile overs' strategy

New Delhi England head coach Brendon McCullum has backed his team to beat India in the upcoming ODI series through their 'hostile overs' strategy. England are set to take on India in a three-match rubber scheduled to begin from February 6 in Nagpur. The Jos Buttler-led side was recently hammered in the T20I series 1-4 and hence will be desperate to turn things around in ODIs ahead of the ICC Champions Trophy 2025.Ahead of the first ODI, McCullum said that he was disappointed after the series loss but expressed confidence in the squad to win the ODI leg. The England head also said that he's excited to see how their hostile overs strategy of going after wickets works out in the ODIs."It's disappointing to lose but Rome wasn't built in a day and the guys are all in on the belief we're trying to achieve. We've seen a pretty clear gameplan of how we want to play. We're trying to bowl hostile overs and I'm fascinated how it's going to play out in 50-over cricket, that level of hostility can last a lot longer. We want wickets constantly, we



understand how vital that can be," said McCullum.England aim to end 40-year drought in IndiaEngland will be boosted by the return of their star batter Joe Root in ODIs who will be playing his first ODI since the World Cup 2023. Root has been in sensational form of late in Test cricket, finishing as the highest run scorer of the format in 2024 with 1556 runs from 17 matches at an average of 55.57.Eangland would hope that Root carries his form in ODIs as well which will hold them in good stead ahead of the Champions Trophy. Meanwhile, India have held the upper hand over England in recent times, having won the last two series against them. Moreover, England have won just one ODI series in India way back in January 1985. Hence, the Jos Buttler-led side will be eager to end their 40-year wait in the upcoming series.



Rakul Preet Singh

Jackky Bhagnani Dance To Kala Chashma At Cousin's Baraat



Jackky Bhagnani's cousin Vicky Bhagnani is getting married to his long-time girlfriend, Nidhi Siddaraj today in Mumbai. Ahead of the pheras, the Bhagnani family left their house to reach the wedding venue. Amid much fanfare, Jackky and his wife Rakul Preet Singh were seen shaking a leg in the baraat. In a video that is going viral, the couple is seen dancing to the song Kala Chashma from the film Baar Baar Dekho. They looked elegant in traditional attires. While Jackky wore a white kurta and black pants, Rakul looked beautiful in an embellished suit.

Vicky Bhagnani's sangeet ceremony took place on Sunday, February 2. Jackky Bhagnani and Rakul Preet Singh attended the event in their traditional best. In one of the viral videos, Jackky was seen posing with his wife in front of the paparazzi stationed outside the venue. While Jackky wore a shimmering black Indo-western outfit, Rakul chose a stunning silver saree.

Other celebrities who attended Vicky and Nidhi's Sangeet ceremony included producer Vashu Bhagnani, music composer Anu Malik, producer Ramesh Taurani with his wife Varsha, Sonakshi Sinha's mother Poonam Sinha with her son Kush Sinha and actress Poonam Dhillon.

From the pictures, it appears that the party's theme was black and silver, with the entire Bollywood crowd dazzling in these two shades. As for Vicky Bhagnani, he is known for his work on projects like Nikita Roy And The Book of Darkness and Badtameez Gill. He is also the co-founder of Nicky Vicky Bhagnani Films. On the professional front, Jackky and Rakul's upcoming film Mere Husband Ki Biwi is set for a grand release on February 21.

Starring Rakul, Arjun Kapoor, and Bhumi Pednekar, the film is directed by Mudassar Aziz. Mere Husband Ki Biwi is backed by Jackky's home production, Pooja Entertainment, and also features Dino Morea and comedian Harsh Gujral in significant roles.



Malaika Arora

Serves Pure Workout Motivation In A Purple Athleisure

Malaika Arora can be easily crowned one of the fashion queens of Bollywood, who takes immense pleasure in working out. She is often spotted shedding a few kilos and sweating it out in the gym. And the result of her rigorous fitness regime is undeniably inspirational. The actress keeps serving goals with her workout journey. Additionally, it is her gym fashion that leaves enthusiasts taking notes. In a video on Instagram, Malaika Arora was seen exiting her residence when she was spotted by the paps stationed outside her home. She was reportedly seen outside her gym while she was heading towards her home in the coolest athleisure. The Kaante actress was wearing purple-hued athleisure. It included a bralette featuring noodle straps, a deep neckline and a criss-cross in the back, accompanied by a pair of body-hugging ankle-length pants.

Malaika teamed her look with a pair of pink slippers and was carrying a sipping bottle in her hand. For accessories, she also picked a pair of black sun shields that added an oomph factor to her look. She kept her makeup minimal and tied her hair in a top-knotted bun hairdo. Altogether, the 51-year-old raised the temperature in her overall gym attire. Undoubtedly, the diva flaunted her toned physique, which served major fitness goals for her fans and others.

In the comments section, one of Malaika's fans wrote, "She is definitely an inspiration." While another person stated, "So pretty," one more user called her "Gorgeous." We must say, despite her age and alleged breakup with Bollywood actor Arjun Kapoor, the diva's glow has remained intact. For those unaware, Malaika was initially married to Salman Khan's brother, Arbaaz Khan, until 2017 when they divorced. The couple has two children from their marriage. After their separation, while Malaika was reportedly dating Arjun, Arbaaz tied the knot with Sshura Khan. Recently, reports surfaced on social media revealing that Malaika had parted ways with her boyfriend, courtesy of their indirect social media posts. Professionally, Malaika has been riding high ever since. She recently launched a lavish restaurant in Mumbai named Scarlett House in Bandra, housed in a 90-year-old Portuguese bungalow. Her close friends and family were even spotted hanging out over there and spending some surreal and scrumptious time.



Boney Kapoor Packed 13 Large Suitcases For Tu Jhoothi Main Makkaar Shoot, Says Khushi Kapoor: 'He Didn't Have Many Scenes'



Khushi Kapoor is gearing up for her big-screen Bollywood debut with Loveyapa, alongside Junaid Khan. Speaking at the SCREEN Live event in New Delhi on Tuesday, she shared a fun insight about her father, producer Boney Kapoor, revealing that despite having two daughters at home, he is actually the "biggest diva." Khushi said, "He is the star of the house, in my opinion. He is bigger than all of us. He is the biggest diva, actor—everything, it's him."

Recalling a hilarious moment from Boney's small role in Tu Jhoothi Main Makkaar, starring Ranbir Kapoor and Shraddha Kapoor, Khushi revealed that he personally selected his outfits and even packed a whopping 13 suitcases for the shoot. She said, "He played a role in Tu Jhoothi Main Makkaar. He didn't have many scenes in the film. He had to shoot in Delhi, and suddenly, I saw 13 large suitcases being moved from his closet. I realized he had packed his entire wardrobe for the film. He wore his own clothes on screen. When I visited him on set, he was dressed in the exact outfit he wears at home, with his boy standing next to him. I thought, 'Is he on a movie set, or is he just chilling at home?' He is the most relaxed and luxurious person I have ever met."

Khushi Kapoor's Loveyapa promises a delightful blend of love, drama, and confusion. Backed by Phantom Studios and AGS Entertainment, the film also features an ensemble cast including Grusha Kapoor, Ashutosh Rana, Tanvika Parlikar, Kiku Sharda, and Kunj Anand. Loveyapa will hit theatres on February 7. This means that it will clash at the box office with Himesh Reshammiya's upcoming film Badass Ravikumar. Meanwhile, Khushi Kapoor will also be seen in Saif Ali Khan and Amrita Singh's son Ibrahim Ali Khan's Bollywood debut, 'Nadaaniyaan'.

Shahid Kapoor Shows His 'No Photography' Hoodie At Mumbai Airport



Shahid Kapoor is currently basking in the glory of his latest film Deva. Recently, the actor was spotted at the Mumbai airport, heading to an undisclosed location. In one of the videos making the rounds online, the Jab We Met actor can be seen exiting his car and walking towards the airport entrance. What caught the netizens' attention was Shahid's sleeveless hoodie. It featured the text, "No Photography," written on the back. Too cool Shahid, too cool.

Meanwhile, Shahid Kapoor's Deva features Pooja Hegde as the female lead. The project has been helmed by Rosshan Andrews. On Monday, the film earned Rs 2.75 crore at the box office, according to industry tracker Sacnilk. So far, Deva has garnered Rs 21.9 crore in the domestic market. Produced by Roy Kapur Films, Deva follows the story of ACP Dev Ambre (Shahid), an impulsive cop and womanizer who loses his



memory while investigating the death of his best friend. Deva is an adaptation of Rosshan's 2013 Malayalam film Mumbai Police, with some changes made to the storyline. Ahead of the release of Deva, Shahid Kapoor conducted an Ask Me Anything session on X (formerly Twitter), where he answered several fans' questions. When asked about his reaction to the film's climax, he shared that he was "shocked post-climax" and found it "very fresh." Shahid Kapoor will be next seen in director Vishal Bhardwaj's upcoming gangster action drama film. Set for release in December 2025, the movie also stars Triptii Dimri, Nana Patekar and Randeep Hooda in important roles. Shahid Kapoor will also reportedly star in Cocktail 2, directed by Homi Adajania. Produced by Maddock Films, the film will be a love triangle.